मुंबई(महाराष्ट्र) से प्रकाशित

हिन्दी दैनिक

उत्तरशक्ति

मुंबई
वर्षः 8 अंक 223
शुक्रवार, 27 फरवरी 2026
मूल्य 3 रुपए, पृष्ठ-6
RNI NO. MAHHIN/2018/76092
email ID- uttarshaktinews@gmail.com
www.uttarshaktinews.com

हर खबर निष्पक्षता के साथ

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की किताब पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, केंद्र को फटकार

नई दिल्ली, 26 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की उस किताब पर पूर्ण और निरपेक्ष प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार'नामक एक अध्याय शामिल था। न्यायालय ने इस मामले को गहरी साजिश करार देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो लोग 'ज्यूडिशियरी करप्शन' पर चैप्टर का ड्राफ्ट बनाने में शामिल हैं, वे UGC या किसी भी मिनिस्ट्री के साथ काम नहीं करेंगे। केंद्र ने बिना शर्त माफी भी मांगी है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, एक सुओ मोटो केस में, हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। इस बीच, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पलटवार करते हुए कहा, मीडिया में हमारे दोस्तों ने यह नोटिस भेजा है। इसमें माफी का एक भी शब्द नहीं है।

जब SG मेहता ने कहा कि 32 किताबें

बिक चुकी थीं लेकिन अब इसे वापस ले लिया गया है, तो उखकने कहा कि यह जानबूझकर किया गया कदम था। CJI ने कहा, पूरी टीचिंग कम्युनिटी को बताया जाएगा कि इंडियन ज्यूडिशियरी करप्ट है और केस पेंडिंग हैं... फिर स्टूडेंट्स, और फिर पेरेंट्स। यह एक गहरी साज़िश है। NCERT की सोशल साइंस बुक के ज्यूडिशियल करप्शन चैप्टर में कहा गया है कि करप्शन, केसों का बहुत बड़ा बैकलॉग, और जजों की सही संख्या की कमी ज्यूडिशियल सिस्टम के सामने आने वाली चुनौतियों में से हैं। नई बुक में कहा गया है कि जज एक कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे होते हैं जो न केवल कोर्ट में उनके व्यवहार को बल्कि कोर्ट के बाहर उनके व्यवहार को भी कंट्रोल करता है। चैप्टर में लिखा है, लोग ज्यूडिशियरी के अलग-अलग लेवल पर करप्शन का अनुभव करते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए, यह न्याय तक पहुंच की समस्या को और खराब कर सकता है। इसलिए, स्टेट और यूनियन लेवल पर ज्यूडिशियल सिस्टम में भरोसा बनाने और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी शामिल है, और जहां भी करप्शन के मामले सामने आएं, उनके खिलाफ तेज और पक्के एक्शन लिए जाएं। किताब में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसों की अनुमानित संख्या 81,000, हाई कोर्ट में 62.40 लाख और डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में 4.70 करोड़ बताई गई है।

पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीती तो हर घुसपैठिया होगा बाहर : अमित शाह

अररिया, 26 फरवरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को विश्वास जताया कि पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जीत दर्ज करेगी और सत्ता में आने के बाद राज्य से हर एक घुसपैठिये को बाहर किया जाएगा। शाह ने यह बात बिहार के अररिया जिले में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। अररिया सीमांचल क्षेत्र में स्थित है, जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है।

उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा जीतने जा रही है। नई सरकार बनने के बाद हम हर एक घुसपैठिये को बाहर करेंगे। गृह मंत्री ने कहा, घुसपैठियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया बिहार, खासकर सीमांचल क्षेत्र से शुरू होगी। हमने पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव इसी मुद्दे पर जीता

था। विरोधियों द्वारा हमारे एजेंडे की आलोचना किए जाने के बावजूद हमें जनादेश मिला। शाह ने कहा कि घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और घुसपैठिये किसी क्षेत्र के जनसांख्यिकीय संतुलन को भी प्रभावित करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वे राशन पर निर्भर रहते हैं और आम लोगों के लिए निर्धारित अन्य लाभों का भी उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम ऐसे जनसांख्यिकीय असंतुलन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं। नरेन्द्र मोदी सरकार जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। शाह ने अपने संबोधन की शुरूआत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की। उन्होंने कहा, 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तब माना गया, जब सावरकर ने इस विषय पर एक पुस्तक लिखकर इसे उसी रूप में स्थापित किया।

यौन उत्पीड़न के आरोपों पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तोड़ी चुप्पी, आरोप लगाने वाले के खिलाफ ही दर्ज कराया मुकदमा

प्रयागराज, 26 फरवरी। प्रयागराज में बटुकों (बालकों) के यौन शोषण के आरोपों को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 22 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया है। शंकराचार्य का कहना है कि कानून के मुताबिक अगर कोई किसी पर झूठा केस करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

शंकराचार्य ने दावा किया कि जिन दो लड़कों के यौन शोषण की बात कही जा रही है, वे लंबे समय से आशुतोष ब्रह्मचारी के पास ही रह रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मेडिकल

रिपोर्ट में बच्चों के साथ गलत होने की पुष्टि हुई है, तो इसका जिम्मेदार वही व्यक्ति है जिसके पास बच्चे रह रहे थे। स्वामी जी ने साफ किया कि उनका उन बच्चों से कोई संपर्क नहीं था और वे कभी उनके गुरुकुल भी नहीं आए।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला है जो जांच को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का हवाला देते हुए कहा कि उनके खिलाफ जानबूझकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के कई साधु-संत उनके साथ हैं, लेकिन सरकार और अपराधियों के डर से वे खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं।

शंकराचार्य ने प्रयागराज की एक महिला द्वारा श्री विद्यामठ को लेकर किए गए दावों को भी गलत बताया। महिला ने मठ में लिफ्ट और स्विमिंग पूल जैसी सुख-सुविधाओं के होने का आरोप लगाया था, जिसे स्वामी जी ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि महिला का परिवार मठ से जुड़ा था, लेकिन जब उन्हें मठ खाली करने को कहा गया, तो वे नाराज होकर झूठे बयान देने लगीं।

होली पर घर जाने वालों के लिए चलेंगी 1244 स्पेशल ट्रेनें: अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली, 26 फरवरी। यदि आप होली पर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने त्योहार के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए बड़ी संख्या में होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, ताकि यात्रियों को कन्फर्म सीट और आरामदायक सफर मिल सके। वहीं अगर आप कोई स्टार्टअप चला रहे हैं और रेलवे के साथ मिलकर नई तकनीक पर काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी अवसर खुल गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई रेल टेक नीति की घोषणा की है, जिसके तहत नवाचार और तकनीकी समाधान सीधे रेलवे से जोड़े जाएंगे।

देखा जाये तो भारतीय रेल अब तेज बदलाव के दौर से गुजर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई रेल टेक नीति और रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल की डिजिटल व्यवस्था की शुरूआत कर सुधारों को नई दिशा दे दी है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म्स विजन के तहत उठाया गया है। नई रेल टेक नीति का मकसद रेलवे में नई तकनीक और नए विचारों को बढ़ावा देना है। अब स्टार्टअप, उद्योग और शिक्षण संस्थान सीधे रेलवे के लिए अपने सुझाव दे सकेंगे। इसके लिए रेल टेक पोर्टल शुरू किया गया है, जहां एक ही चरण में प्रस्ताव जमा किए जा सकेंगे। प्रोटोटाइप बनाने और परीक्षण के लिए मिलने वाला अनुदान पहले से दोगुना कर दिया गया है, जबकि स्केल अप के लिए अनुदान तीन गुना से अधिक बढ़ाया गया है।

साथ ही रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल की 23 पीठों को डिजिटल रूप से जोड़ने की तैयारी है। अब यात्री देश में कहीं से भी ऑनलाइन मामला दर्ज कर सकेंगे। इससे सुनवाई की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और आसान होगी। रेल मंत्री ने 2026 में 52

सप्ताह में 52 सुधार लागू करने की योजना भी सामने रखी है। इसमें ट्रैक और ढांचे का विस्तार, बेहतर रखरखाव, नेटवर्क क्षमता बढ़ाना, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और खानपान सेवाओं में सुधार शामिल है। लक्ष्य है कि रेल दुर्घटनाओं की संख्या को घटाकर एक अंक तक लाया जाए। बाइट।

इधर, होली के त्योहार को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ी तैयारी की है। 25 फरवरी से 18 मार्च 2026 के बीच 1244 होली विशेष रेल यात्राएं चलाई जाएंगी। जरूरत पड़ने पर यह संख्या 1500 तक बढ़ाई जा सकती है। इन विशेष ट्रेनों से मुंबई, पुणे, नागपुर, पटना, दरभंगा, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, अमृतसर, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली समेत कई प्रमुख शहरों के बीच अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी। पूर्व मध्य रेलवे सबसे अधिक 275 विशेष यात्राएं चलाएगा, जबकि उत्तर रेलवे 204 यात्राएं संचालित करेगा। इसके अलावा पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और अन्य सभी जोन में भी विशेष सेवाएं चलाई जाएंगी। रेल मंत्रालय का कहना है कि इन विशेष ट्रेनों से नियमित ट्रेनों पर दबाव कम होगा और यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी।

देखा जाये तो भारतीय रेल एक साथ दो मोर्चों पर काम कर रही है। एक ओर तकनीक और प्रशासनिक सुधारों से व्यवस्था को आधुनिक बनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर त्योहारों के समय यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इससे साफ है कि रेलवे अब सुरक्षा, सुविधा और सुधार को साथ लेकर आगे बढ़ रही है।

वायनाड भूस्खलन पीड़ितों से बोले राहुल गांधी कांग्रेस बनवाकर देगी 100 नए घर

नई दिल्ली, 26 फरवरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को साल 2024 में आए भीषण भूस्खलन के पीड़ितों के लिए एक बड़ी राहत योजना की शुरूआत की। उन्होंने पार्टी की ओर से बनाए जाने वाले 100 घरों का शिलान्यास किया।

कांग्रेस द्वारा बनाए जा रहे ये घर 1,100 स्क्वायर फीट के होंगे, जिनमें से हर घर के लिए 8 सेंट जमीन दी गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि उनका पूरा परिवार उन लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है जिन्होंने इस त्रासदी में अपना सब कुछ खो दिया है। राहुल गांधी ने पीड़ितों की हिम्मत की सराहना करते हुए कहा, 'आपने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अपना हौसला और दूसरों के प्रति हमदर्दी नहीं खोई।' उन्होंने घर बनाने की प्रक्रिया में हुई देरी का भी जिक्र किया

और बताया कि जमीन की परमिशन और अन्य कागजी कार्रवाई के कारण समय लगा, लेकिन अब यह काम जल्द पूरा होगा। उन्होंने इस पहल को पीड़ितों के लिए प्यार और साथ का एक संदेश बताया।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पीड़ितों का दुख साझा करते हुए कहा कि उन्होंने उन लोगों की मुश्किलें देखी हैं जिन्होंने अपने परिजनों और खेतों को खो दिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के सभी सांसदों ने गृह मंत्री से मिलकर इसे 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित करने की मांग की थी और प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा था।

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद शिक्षा मंत्री का कड़ा रुख, दोषियों पर होगी कार्रवाई

नई दिल्ली। कक्षा 8 की एनसीईआरटी किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' नामक पाठ को लेकर विवाद गहरा गया है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है, जिसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान सामने आया है झारखंड के सरायकेला खरसावां में मीडिया से बात करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनसीईआरटी की किताबों में न्यायपालिका के बारे में ऐसी बातें लिखना चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि मामला सामने आते ही किताबों का रिव्यू कराया गया है। शिक्षा मंत्री ने इस घटना पर गहरा अफसोस जताया और भरोसा दिया कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

DAKS REHAB CENTRE
(PARALYSIS PHYSIOTHERPHY CENTER AND OLD AGE HOME)
Contact us: 9820519851
विल्डिंग नंबर 3, प्लॉट नंबर 3, आदर्श घरकुल सोसायटी सायन कोलीवाडा जीटीबी नगर मुंबई-37

* Stroke/Paralysis/Complete Rehab Centre
* बाहर से आये रोगी और उनके परिजनो के ठहरने कि व्यवस्था
* वृद्ध लोगों के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध
* DM/HT/THYROID इन सब से कैसे बचें
* NGO में मिलनेवाली सहायता को लोगों में देना
* चिकित्सा उपकरणो को किराये और बिक्री सुविधा उपलब्ध
* एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध
* पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब सेंटर
* मरीजों के लिए घर पर 12 और 24 घंटे जीडीए परिचारक
* विशेषज्ञ डॉक्टरो से ऑनलाइन और ऑफलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध
* मासिक ईएमआई के आधार पर व्यक्तीयों, परिवारो और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य निती की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध

NEW LIGHT CLASSES
TRADITION OF EXCELLENCE
2nd Floor, Sheetal Bldg.
Near Diamond Talkies,
L. T. Road, Borivali (West)
Mumbai - 400 092
Maharashtra

ADMISSIONS OPEN
ALL OVER INDIA
ENROLL NOW

SMART CLASSROOM
(ONLINE/OFFLINE)
Courses Offered
Std. XI & XII (Sci.)
NEET
JEE (Main & Advance)
MHT-CET
Polytechnic & Engg
Physics and Maths (ICSE, CBSE, ISC)
M: 9833240148 | E: edu@newlightclasses.com | W: www.newlightclasses.com

शिक्षा में न्यायपालिका: संवाद की जरूरत या विवाद की राजनीति?

-ललित गर्ग

एक बार फिर शिक्षा से जुड़ा एक प्रश्न राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में है। शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा प्रकाशित आठवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका शीर्षक अध्याय में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और लंबित मुकदमों का उल्लेख किए जाने पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी प्रकट की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की यह टिप्पणी कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने नहीं दिया जाएगा केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि संस्थागत गरिमा की रक्षा का संकेत है। इसके बाद संबंधित अध्याय को हटाने और बाजार में उपलब्ध पुस्तकों को वापस लेने का निर्णय लिया गया। प्रश्न यह है कि क्या यह केवल एक संपादकीय चूक थी या हमारे शैक्षिक ढांचे में कहीं गहरी संरचनात्मक कमी है? प्रश्न है कि स्कूली बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी देने से किस हित की पूर्ति होने वाली है? लेकिन इसमें दो मत नहीं

है कि न्यायिक तंत्र के साथ हर क्षेत्र में फैली भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के ठोस उपाय होने ही चाहिए। सबसे पहले यह भी स्वीकार करना होगा कि न्यायपालिका में लंबित मामलों और भ्रष्टाचार जैसे प्रश्न पूरी तरह काल्पनिक नहीं हैं। न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या करोड़ों में है, यह एक सार्वजनिक तथ्य है। कुछ मामलों में न्यायिक आचरण पर भी प्रश्न उठे हैं। परंतु उतना ही सत्य यह भी है कि भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर अपनी स्वतंत्रता, पारदर्शिता और सक्रियता से लोकतंत्र की रक्षा की है। पिछले वर्षों में शीर्ष न्यायाधीशों द्वारा अपनी संपत्तियों का सार्वजनिक विवरण देने की सहमति जैसे कदमों ने संस्थागत पारदर्शिता को सुदृढ़ किया है। ऐसे में प्रश्न यह नहीं है कि समस्या है या नहीं, प्रश्न यह है कि उसे किस भाषा, किस संतुलन और किस शैक्षिक दृष्टि से प्रस्तुत किया जाए।

शिक्षा का उद्देश्य केवल तथ्य देना नहीं, दृष्टि देना है। यदि हम बच्चों को यह सिखाते हैं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, तो साथ ही यह भी सिखाना होगा कि न्यायपालिका ने भ्रष्टाचार से लड़ने में कैसी भूमिका निभाई है, उसने प्रशासनिक दुरुपयोग पर कैसे अंकुश लगाया है, नागरिक अधिकारों की रक्षा में कैसे ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। शिक्षा में आलोचना हो, पर निराशा नहीं, तथ्य हों, पर संतुलन भी हो। यदि किसी अध्याय में केवल संस्थागत विकृतियों का उल्लेख हो और सुधारात्मक प्रयासों, आदर्श उदाहरणों और संवैधानिक मूल्यों का समुचित विवेचन न हो, तो वह शिक्षा में मूल्यों एवं आदर्शों के बजाय अविश्वास का बीजारोपण बन सकता है। यह विवाद एक बड़े प्रश्न को भी जन्म देता है-पाठ्य पुस्तकों की निर्माण प्रक्रिया में बहुस्तरीय समीक्षा के बावजूद ऐसी सामग्री कैसे प्रकाशित हो जाती है? क्या संपादकीय बोर्ड में विविध दृष्टिकोणों का अभाव है? क्या विधि विशेषज्ञों, शिक्षाशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों के बीच समन्वय पर्याप्त नहीं है? एक लोकतांत्रिक समाज में संस्थाओं की आलोचना वर्जित नहीं हो सकती, पर आलोचना और अवमूल्यन के बीच महीन रेखा होती है। शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी जैसी संस्थाओं का दायित्व है कि वे इस रेखा को पहचानें।

यह भी स्मरणीय है कि भ्रष्टाचार केवल न्यायपालिका तक सीमित समस्या नहीं है। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इसी महीने जारी रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 182 देशों के बीच भारत की रैंक 91 है। पिछले साल के मुकाबले भारत ने 5 स्थान का सुधार किया है, यह स्थिति सुधार के बावजूद मध्य स्तर पर बनी हुई बताई गई है। इसका अर्थ है कि भ्रष्टाचार एक संरचनात्मक, सामाजिक और प्रशासनिक चुनौती है। यदि हम बच्चों को इसके बारे में पढ़ाते हैं तो उसे एक समग्र सामाजिक संदर्भ में पढ़ाया जाना चाहिए कि यह समस्या क्यों उत्पन्न होती है, इसे रोकने के लिए क्या संवैधानिक तंत्र हैं, नागरिकों की क्या भूमिका है और सुधार की संभावनाएं क्या हैं। केवल किसी एक संस्था को केंद्र में रखकर समस्या का चित्रण करना न तो शैक्षिक रूप से न्यायोचित है और न ही संवैधानिक संतुलन के अनुरूप।

न्यायपालिका की गरिमा का प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र तीन स्तंभों-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर आधारित है। यदि किसी एक स्तंभ के प्रति बच्चों के मन में अविश्वास की भावना बिना सम्यक विश्लेषण के उत्पन्न हो जाए, तो यह दीर्घकाल में लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए हानिकारक हो सकता है। परंतु गरिमा की रक्षा का अर्थ यह भी नहीं कि समस्याओं पर मौन साध लिया जाए। गरिमा और पारदर्शिता परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। न्यायपालिका की वास्तविक प्रतिष्ठा उसकी आलोचना सहने की क्षमता, आत्मसुधार की तत्परता और नैतिक दृढ़ता से बढ़ती है। इस संदर्भ में एक नई शैक्षिक संरचना की आवश्यकता अनुभव होती है। पाठ्य पुस्तकों में संस्थागत अध्ययन का प्रारूप इस प्रकार विकसित किया जा सकता है जिसमें तीन आयाम हों-संविधान द्वारा प्रदत्त भूमिका, वास्तविक चुनौतियां और सुधार की पहल। उदाहरण के लिए, न्यायपालिका पर अध्याय में उसके ऐतिहासिक निर्णय, जनहित याचिका की परंपरा, मौलिक अधिकारों की रक्षा, साथ ही लंबित मामलों की समस्या और न्यायिक सुधार आयोगों की सिफारिशों का संतुलित उल्लेख किया जाए। इससे छात्र न तो अंधभक्त बनेंगे और न ही निंदक, वे सजग नागरिक बनेंगे।

शिक्षा मंत्रालय को भी इस अवसर को आत्ममंथन के रूप में लेना चाहिए। विवाद के बाद अध्याय हटाना तात्कालिक समाधान हो सकता है, पर स्थायी समाधान नहीं। आवश्यकता है एक स्वतंत्र, बहुविषयी समीक्षा तंत्र की, जिसमें विधि विशेषज्ञ, पूर्व न्यायाधीश, शिक्षाशास्त्री, समाजशास्त्री और बाल मनोविज्ञान के जानकार शामिल हों। साथ ही, सार्वजनिक परामर्श की परंपरा विकसित की जा सकती है ताकि पाठ्य पुस्तकें केवल सरकारी दस्तावेज न रहकर सामाजिक सहमति का दस्तावेज बनें। न्यायपालिका भी इस प्रसंग में रचनात्मक पहल कर सकती है। यदि वह स्वयं विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए न्यायिक साक्षरता कार्यक्रम आरंभ करे, न्यायालयों के कार्यप्रणाली पर सरल और संतुलित अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराए, तो इससे भ्रांतियों का निवारण होगा। न्यायपालिका की पारदर्शिता और संवादशीलता उसकी गरिमा को और सुदृढ़ करेगी।

अंततः यह विवाद हमें यह सोचने को विवश करता है कि हम अपने बच्चों को कैसी नागरिकता का संस्कार देना चाहते हैं। क्या हम उन्हें केवल समस्याओं का बोध देंगे या समाधान की प्रेरणा भी देंगे? क्या हम उन्हें संस्थाओं पर अविश्वास करना सिखाएँगे, या सुधार में सहभागी बनने की चेतना से सम्पन्न बनायेंगे? लोकतंत्र का भविष्य पाठ्य पुस्तकों की पंक्तियों में ही आकार लेता है। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा में सत्य हो-पर संतुलित, आलोचना हो-पर रचनात्मक और संस्थाओं की गरिमा अक्षुण्ण रखते हुए सुधार की राह भी खुली रहे। भ्रष्टाचार एक गंभीर राष्ट्रीय चुनौती है, पर उसका समाधान संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर देने से नहीं, बल्कि उन्हें अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बनाकर ही निकलेगा। शिक्षा का कार्य इसी संतुलन को साधना है। यदि यह विवाद हमें अधिक परिपक्व, संवादशील और उत्तरदायी शैक्षिक व्यवस्था की ओर ले जाए, तो यह एक नई दिशा, नई दृष्टि और नई संरचना के प्रादुर्भाव का अवसर सिद्ध हो सकता है। लोकतंत्र की सच्ची शक्ति आलोचना और आत्मसुधार के समन्वय में ही निहित है, और यही संतुलन हमारी पाठ्य पुस्तकों में भी प्रतिबिंबित होना।

-सुरेश गांधी

उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सनातन और अहंकार जैसे शब्द केवल आध्यात्मिक विमर्श तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि वे राजनीतिक बहस के केंद्र में आ खड़े हुए हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हालिया बयान, अहंकारी कभी सनातनी नहीं हो सकता ने सियासी गलियारों में नई चर्चा को जन्म दिया है। इस बयान को कई राजनीतिक विश्लेषक प्रदेश की वर्तमान सत्ता और हालिया संत-सम्बंधित विवादों से जोड़कर देख रहे हैं। यह विवाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े हालिया प्रकरण के संदर्भ में चर्चा में है। बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया। सत्तापक्ष के समर्थकों ने इसे आस्था पर राजनीति का आरोप बताते हुए पलटवार किया, वहीं विपक्ष ने इसे वैचारिक टिप्पणी बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही नीतियों, विशेषकर धार्मिक स्थलों के विकास, गौ-संरक्षण और कानून-व्यवस्थाकृको लेकर भी बहस फिर से तेज हो गई है

फिरहाल, उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों केवल नीतियों और योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि छवि, विचारधारा और सोशल मीडिया नैरेटिव के इर्द-गिर्द एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। एक ओर विपक्षी बयानबाजी है, तो दूसरी ओर समर्थकों द्वारा प्रस्तुत विकास और प्रशासनिक मॉडल का दावा। इसी क्रम में सोशल मीडिया पर एक संदेश तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जब किसी राज्य का शासक एक संन्यासी होता है तब उस राज्य का कल्याण अवश्य होता है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से फेसबुक, एक्स और अन्य डिजिटल मंचों पर राजनीतिक वार-प्रतिवार का सिलसिला तेज हुआ है। एक तरफ समाजवादी राजनीति से जुड़े बयान चर्चा में हैं, तो दूसरी ओर समर्थक योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को निराशा से आशा तक की यात्रा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह पूरा विमर्श बताता है कि अब राजनीति केवल धरातल पर ही नहीं, बल्कि डिजिटल मंचों पर भी आकार ले रही है।

मतलब साफ है राजनीतिक विमर्श का एक बड़ा केंद्र अयोध्या धाम और उससे जुड़े ऐतिहासिक संदर्भ रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियों और वर्तमान प्रशासनिक दृष्टिकोण की तुलना करते हुए दोनों पक्ष अपने-अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। किसानों के बीच छुट्टा पशुओं की समस्या, अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई और सामाजिक प्रभाव जैसे मुद्दे भी इसी बहस का हिस्सा बन गए हैं। दरअसल, उत्तर प्रदेश की राजनीति में धार्मिक प्रतीकों का प्रभाव नया नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में यह विमर्श और अधिक मुखर हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है क्या आस्था को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का आधार बनाया जाना चाहिए या इसे सांस्कृतिक परंपरा के रूप में राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए। खासकर चुनावी माहौल के करीब आते ही शब्दों का यह संघर्ष और तीखा हो सकता है। परंतु लोकतंत्र की परिपक्वता इसी में है कि मतभेदों के बीच संवाद बना रहे और आस्था का विषय सामाजिक समरसता को मजबूत करने का माध्यम बने, न कि विभाजन का।

अखिलेश के बयान पर बृजलाल का पलटवार

सनातन और समकालीन राजनीति को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व डीजीपी एवं राज्यसभा सांसद बृजलाल ने सोशल मीडिया पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि अखिलेश यादव को सनातन पर टिप्पणी करने से पहले इतिहास को याद करना चाहिए।

1990 की घटनाओं का उल्लेख

बृजलाल ने अपने वक्तव्य में कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को 7 मई 1990 को तत्कालीन सरकार के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जिसे उन्होंने सनातन परंपरा के इतिहास की अभूतपूर्व घटना बताया। उस समय उत्तर प्रदेश में सरकार का नेतृत्व मुलायम सिंह यादव कर रहे थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उस दौर में अयोध्या धाम में कारसेवा से जुड़े घटनाक्रमों ने व्यापक राजनीतिक विवाद को जन्म दिया और 1990 की गोलीकांड घटनाओं का उल्लेख करते हुए समाजवादी राजनीति पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए।

राजनीतिक विमर्श में सनातन का प्रश्न

पूर्व डीजीपी बृजलाल ने अपने बयान में कहा कि धार्मिक आस्था और राजनीतिक विमर्श को लेकर भ्रम फैलाना उचित नहीं है और जनता इतिहास को भली-भांति जानती है। उन्होंने यह भी कहा कि सनातन परंपरा को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने के बजाय सांस्कृतिक दृष्टि से समझा जाना चाहिए।

संन्यास और सत्ताः भारतीय परंपरा का संदर्भ

भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में संन्यास का अर्थ केवल वैराग्य नहीं, बल्कि अनुशासन, त्याग और लोककल्याण से भी जोड़ा गया है। प्राचीन ग्रंथों में राजधर्म और धर्मनीति का उल्लेख मिलता है, जहां शासक को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के हित में कार्य करने वाला माना गया है। यही कारण है कि जब कोई संन्यासी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाता है, तो उसकी कार्यशैली को सामान्य राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग मानकर देखा जाता है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और जटिल राज्य में प्रशासनिक चुनौतियां हमेशा से बड़ी रही हैं। जनसंख्या, भौगोलिक विस्तार, सामाजिक विविधता और आर्थिक असमानता जैसे कारकों ने यहां शासन को कठिन बनाया है। ऐसे में जब एक धार्मिक पृष्ठभूमि से आए नेता ने शासन की कमान संभाली, तो स्वाभाविक रूप से अपेक्षाएं भी अधिक रहीं।

बदलती छवि : कानून-व्यवस्था से निवेश तक

योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को लेकर समर्थक सबसे अधिक जिस विषय को रेखांकित करते हैं, वह कानून-व्यवस्था में सुधार का दावा है। अपराध नियंत्रण, संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई और प्रशासनिक सख्ती को उनके शासन की पहचान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ ही औद्योगिक निवेश को लेकर भी सरकार लगातार सक्रिय रही है। निवेश शिखर सम्मेलनों, एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं और औद्योगिक कॉरिडोर के माध्यम से राज्य को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने की कोशिशें राजनीतिक विमर्श का प्रमुख हिस्सा बनी हैं। सरकार समर्थक यह दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश अब देश की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से उभर रहा है और इसे भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि आर्थिक आंकड़ों को लेकर विशेषज्ञों की अलग-अलग राय भी सामने आती रही है, लेकिन यह स्पष्ट है कि विकास का नैरेटिव राजनीतिक संवाद का केंद्रीय तत्व बन चुका है।

महिला सुरक्षा का मुद्दा और राजनीतिक संदेश

सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे संदेशों में महिला सुरक्षा को विशेष रूप से रेखांकित किया जा रहा है। बेटियों में सम्मान और स्वाभिमान जैसे वाक्य राजनीतिक प्रचार का हिस्सा बनते जा रहे हैं। एंटी-रोमियो स्क्वॉड, मिशन शक्ति और महिला हेल्पलाइन जैसी योजनाओं को सरकार की उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी ओर विपक्ष इन दावों की समीक्षा करते हुए वास्तविक आंकड़ों और घटनाओं का हवाला देता है। इस प्रकार महिला सुरक्षा का मुद्दा भी राजनीतिक विमर्श का प्रमुख आधार बन गया है।

सोशल मीडिया का नया राजनीतिक रणक्षेत्र

डिजिटल प्लेटफॉर्म ने राजनीति की शैली बदल दी है। पहले जहां बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहते थे, वहीं अब हर विचार कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ॥अहंकार और सनातन॥ संबंधी बयान के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। समर्थकों और विरोधियों दोनों ने अपने-अपने तर्कों के साथ पोस्ट, वीडियो और ग्राफिक्स साझा किए। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक डिजिटल मंचों पर लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले चुनावों में सोशल मीडिया की भूमिका और निर्णायक हो सकती है।

आस्था बनाम राजनीति : बहस का विस्तार

सनातन, मंदिर, धार्मिक प्रतीक और सांस्कृतिक पहचान, ये सभी विषय उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से प्रभावी रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इनका प्रभाव और अधिक स्पष्ट हुआ है। समर्थक योगी आदित्यनाथ की छवि को संन्यासी प्रशासक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक ब्रांडिंग बताता है। यही कारण है कि हर बयान के साथ वैचारिक बहस भी तेज हो जाती है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, आस्था और प्रशासन का संतुलन ही किसी भी सरकार की दीर्घकालिक स्वीकार्यता तय करता है।

छुट्टा पशु, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जमीनी चुनौतियां

जहां एक ओर विकास और निवेश की चर्चा होती है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में छुट्टा पशुओं की समस्या भी राजनीतिक बहस का विषय बनी हुई है। किसानों की फसलों को नुकसान, गौशालाओं की व्यवस्था और पशु संरक्षण के व्यावहारिक पक्ष को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आते रहे हैं। विपक्ष इसे सरकार की नीति से जोड़कर सवाल उठाता है, जबकि सत्तापक्ष इसे संक्रमणकालीन समस्या बताकर समाधान के प्रयासों की बात करता है। यह स्पष्ट करता है कि जमीनी मुद्दे अभी भी राजनीतिक विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

छवि निर्माण और नेतृत्व की राजनीति

राजनीति में नेतृत्व की छवि हमेशा निर्णायक रही है। योगी आदित्यनाथ को समर्थक ॥निर्णायक॥ और ॥अनुशासित॥ नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वहीं विपक्ष उन्हें कठोर प्रशासनिक शैली वाला नेता बताता है। छवि निर्माण का यह दौर केवल भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि योजनाओं, कार्यक्रमों और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से लगातार मजबूत किया जा रहा है।

डिजिटल युग में नैरेटिव की शक्ति

आज राजनीति में केवल कार्य करना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि उस कार्य को प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। यही कारण है कि सोशल मीडिया टीम, डिजिटल अभियान और ट्रेंडिंग पोस्ट अब राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल नैरेटिव कई बार वास्तविक मुद्दों से भी अधिक प्रभाव डालता है, क्योंकि वह भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। विपक्ष की रणनीति और वैचारिक टकराव

अखिलेश यादव लगातार सामाजिक न्याय, आर्थिक मुद्दों और किसानों की समस्याओं को उठाते रहे हैं। उनकी राजनीति विकास और सामाजिक समीकरणों के संतुलन पर आधारित बताई जाती है। वहीं सत्तापक्ष सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और प्रशासनिक सख्ती को अपनी प्रमुख पहचान के रूप में प्रस्तुत करता है। यही वैचारिक अंतर उत्तर प्रदेश की राजनीति को लगातार गतिशील बनाए हुए है।

क्या संन्यासी नेतृत्व का मॉडल टिकाऊ है?

यह प्रश्न राजनीतिक विश्लेषण का महत्वपूर्ण विषय बन चुका है कि क्या धार्मिक पृष्ठभूमि से आए नेतृत्व का मॉडल लंबे समय तक राजनीतिक रूप से प्रभावी रह सकता है। कुछ विशेषज्ञ इसे भारतीय परंपरा से जुड़ा मॉडल मानते हैं, जबकि कुछ इसे राजनीतिक प्रयोग बताते हैं। लेकिन यह निर्विवाद है कि योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग शैली लेकर आया है।

बहस जारी रहेगी

सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे संदेश, राजनीतिक बयान और वैचारिक प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। यहां विकास, आस्था, पहचान और नेतृत्वकृसभी मिलकर राजनीतिक विमर्श को आकार दे रहे हैं। संभव है कि आने वाले समय में यह बहस और तीखी हो, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि विभिन्न विचारों के बीच संवाद चलता रहे। अंततः जनता ही तय करती है कि कौन सा मॉडल और कौन सा नेतृत्व उसके भविष्य की दिशा तय करेगा। राजनीति के इस बदलते परिदृश्य में इतना तय है कि संन्यास, सत्ता और सोशल मीडिया, इन तीनों का संगम आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की राजनीति को और रोचक तथा निर्णायक भूमिका होंगे.

चंद्रशेखर आजाद : क्रांति, साहस और आत्मसम्मान की अमर गाथा

-सुनील कुमार महला

-सुनील कुमार महला

27 फरवरी को महान क्रांतिकारी, अदम्य साहस, अटूट देशभक्ति और आत्मसम्मान के प्रतीक चंद्रशेखर आजाद का शहीद दिवस है। पाठकों को बताता चलूं कि वर्ष 1931 में इसी दिन उन्होंने इलाहाबाद (अब प्रयागराज) के चंद्रशेखर आजाद पार्क (तत्कालीन अल्फ्रेड पार्क) में अंग्रेजों से घिर जाने पर वीरगति प्राप्त की।

उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिला में हुआ था तथा उनका बचपन झाबुआ जिले के भाबरा गाँव में बीता, जहाँ उनके अधिकांश मित्र भील जनजाति के बालक थे। उनके साथ रहते हुए उन्होंने बचपन में ही धनुष-बाण चलाने में दक्षता हासिल कर ली, जो आगे चलकर उनकी अचूक निशानेबाजी का आधार बनी।

पाठकों को बताता चलूं कि उनका वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था और आजाद नाम उन्होंने स्वयं अदालत में घोषित किया था। दिसंबर 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने अपना नाम 'आजाद', पिता का नाम 'स्वतंत्रता' और पता 'जेलखाना' बताया। सजा के रूप में उन्हें 15 कोड़े लगाए गए, जिसके बाद से वे ॥आजाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए।

उनकी माता जगरानी देवी चाहती थीं कि वे संस्कृत के विद्वान बनें, इसलिए उन्हें पढ़ाई के लिए वाराणसी के काशी विद्यापीठ भेजा गया। किंतु जलियांवाला बाग हत्याकांड(13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में) ने उनकी सोच बदल दी और वे क्रांतिकारी मार्ग पर चल पड़े। उनकी जुबां पर अक्सर एक शेर रहता था-'दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे,आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे।' पाठक जानते होंगे कि आजाद ने शपथ ली थी कि वे कभी अंग्रेजों के हाथ जीवित नहीं पकड़े जाएंगे, और उन्होंने अंत तक अपने इस वचन को निभाया भी। वे भेष बदलने की कला में अत्यंत निपुण थे तथा कई बार पुलिस के सामने से निकल गए और उन्हें पता भी नहीं चला। कहते हैं कि एक बार उन्होंने स्त्री का भेष धारण कर अंग्रेजों को चकमा दे दिया था। पुलिस से बचने के लिए वे साधु/संन्यासी बनकर भी रहे और बच्चों को पढ़ाया। झांसी के पास ओरछा के जंगलों में उन्होंने 'पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी' नाम से संन्यासी रूप में निवास किया तथा साथियों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया। उनकी फुर्ती और तेज दिमाग के कारण साथी उन्हें 'क्विक सिल्वर' (पारा) कहते थे।

वे क्रांतिकारी संगठन के वरिष्ठ नेता थे और युवाओं को प्रशिक्षण देते थे, जिनमें भगत सिंह भी शामिल थे। पाठकों को बताता चलूं कि भगत सिंह उन्हें सम्मान से 'पंडित जी' कहते थे। दोनों की जोड़ी को 'आग और हवा' की तरह माना जाता था-जहाँ भगत सिंह वैचारिक रूप से गहरे थे, वहीं आजाद संगठन संचालन और क्रांतिकारी कार्रवाई में निपुण थे। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने के बाद वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (एचआरए) से जुड़े। गौरतलब है कि यह संगठन 1924 में शचींद्र नाथ सान्याल सहित अन्य क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित किया गया था। इसके प्रमुख सदस्यों में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी आदि शामिल थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने हेतु 1925 में काकोरी ट्रेन कार्रवाई की गई। बाद में संगठन का पुनर्गठन कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (एचएसआरए) बनाया गया, जिसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर और जोगेश चंद्र चटर्जी सहित अन्य साथियों ने की। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आजाद 1929 में लॉर्ड इरविन की ट्रेन पर बम फेंकने की योजना में भी शामिल थे।

27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने अपने साथी सुखदेव राज को सुरक्षित निकल जाने का अवसर दिया और स्वयं लगभग 40 मिनट तक अकेले पुलिस से लोहा लेते रहे। उस समय उनके पास केवल एक छोटी कोल्ट पिस्तौल थी। जब अंतिम गोली बची, तो अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए उन्होंने स्वयं को गोली मार ली और वीरगति प्राप्त की।जानकारी मिलती है कि उनकी मृत्यु के बाद भी ब्रिटिश पुलिस उनके पास जाने से डर रही थी। पुष्टि करने के लिए दूर से उनके शरीर पर गोलियाँ चलाई गईं, तब जाकर वे पास पहुँचे। आजाद अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि कई बार संगठन के लिए धन बचाने हेतु स्वयं भूखे रह जाते थे, लेकिन अपने साथियों की जरूरतें वे पहले पूरी करते थे। उनकी शहादत के बाद काफी समय तक उनकी माता को पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, ताकि उन्हें गहरा सदमा न पहुँचे। निष्कर्षतः, चंद्रशेखर आजाद ने अपना सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने युवाओं को यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता, स्वाभिमान और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प, त्याग और साहस से असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

जब किसान मजबूत तो देश मजबूत?

-विक्रम दयाल

जब किसान मजबूत होते हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, और उनकी मेहनत से ही हमारा देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनता है। किसानों की मजबूती से देश को कई फायदे होते हैं: खाद्यान्न सुरक्षाः मजबूत किसान देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाते हैं, जिससे देश की खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित होती है। आर्थिक विकासःकिसानों की आय बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, जिससे देश को आर्थिक विकास में७ योगदान होता है। रोजगार सृजनः कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन होता है। निर्यात बढ़ावाः किसानों की मेहनत से देश को कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलता है, जिससे देश की विदेशी मुद्रा आय बढ़ती है। लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार और समाज को कई कदम उठाने होंगे। किसानों को उचित मूल्यः किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलना चाहिए, ताकी उनकी आय बढ़ सके। कृषि तकनीक का प्रसारः किसानों को नई कृषि तकनीकों के बारे मैं जानकारी देनी चाहिए, ताकि वे अपनी उत्पादकता बढ़ा सकें। कृषि ऋण और वीमाः किसानों को सस्ते ऋण और फसल बीमा की सुविधा मिलनी चाहिए, ताकि वे अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकें। कृषि इनफ्रास्टकचरः सरकार को कृषि इनफ्रास्टचर में निवेश करना चाहिए, ताकि सिचाई व्यवस्था, सड़कें, और बाजारों का विकास। इसके अलावा किसानों की समस्याएंः- कम आयः किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नही मिलता है, जिससे उनकी आय कम होती है। कृषि लागत में वृद्धिः कृषि लागत में वृद्धि से किसानों की आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फसल की विफलताः प्राकृतिक आपदाओं, जैसे कि सूखा, बाढ़,और ओलावृष्टि से फसलों की विफलता हो सकती है। कृषि ऋणः किसानों को सस्ते ऋण की सुविधा नही मिलती है, जिससे वे अपनी फसलों को सुरक्षित नही रख सकते। कृषि इनफ्रास्टकचर की कमीः कृषि इनफ्रास्टकचर की कमी से किसानों को अपनी फसलों को बाजार तक पहुँचाने मैं परेशानी होती है। किसानों की मेहनत से देश की आत्मनिर्भरताः-- खाद्यान सुरक्षाः किसानों की मेहनत से देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाता है, जिससे देश की खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित होती है। आर्थिक विकासः किसानों की आय बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, जिससे देश के आर्थिक विकास में योगदान होता है। रोजगार सृजनः कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन होता है। निर्यात बढ़ावाः किसानों की मेहनत से देश के कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलता है, जिससे देश की विदेशी आय मुद्रा बढ़ती है।

राष्ट्र हित सर्वोपरि

-डॉ. सुधाकर आशावादी-विभूति फीचर्स

सदियों से अस्पृश्यता और भेदभाव के कि स्से प्रकाश में आते रहे हैं। सामाजिक संरचना में बरसों से पारिवारिक एवं सांस्कृतिक उत्सवों में सभी की भागीदारी सुनिश्चित थी। सभी के साझा प्रयास से ग्रामीण अर्थ व्यवस्था सुचारु रूप से चलती थी। कुछ क्षेत्रों में भेदभाव के कि स्से प्रकाश में आते थे। वर्तमान में अस्पृश्यता, छुआ-छूत और भेदभाव व्यवहार में दिखाई नही देते, अलबत्ता अनेक संगठन सामाजिक समरसता स्थापित करने के प्रयास में जुटे रहते हैं। इस कड़ी में अपनी स्थापना के उपरांत सौ बरस के कार्यकाल में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जनसेवा के प्रति जो स्वरूप खड़ा हुआ है। उसमें किसी भी स्तर पर जातीय भेदभाव लक्षित नही होता, फिर भी समाज में जातीय भेदभाव पर आधारित विमर्श प्रचलित है। जातीय भेदभाव वास्तव में है या किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसे बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जा रहा है, इसकी स्थिति स्पष्ट नही है। कुछ राजनीतिक दल तो संकीर्ण जातीयता के प्रतिनिधि बनकर समाज में जातीय गणना किए जाने की वकालत करते है, जिसके पीछे उनका तर्क यही है, कि जातीय गणना से विभिन्न जातियों की समाज में हिस्सेदारी स्पष्ट हो तथा सभी को जातीय आधार पर सुविधाएँ मिलें। बहरहाल विश्व के किसी भी देश में नागरिकों की गणना जातीय आधार पर की जाती हो, ऐसा प्रतीत नही होता। जहां तक भेदभाव का प्रश्न है, तो कहा जा सकता है, कि भेदभाव व्यक्तिगत आधार पर तो संभव है, जातीय आधार पर नही।

मुंबई भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से शिक्षण समिति की अध्यक्षा को दी गई बधाई

मुंबई (उत्तरशक्ति)। मुंबई महानगरपालिका शिक्षण समिति के अध्यक्ष पद पर गत दिनों श्रीमती राजश्री शिरवाडकर चुनी गई। राजश्री शिरवाडकर के शिक्षण समिति के अध्यक्ष पद पर विराजमान होने पर शैक्षणिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की ओर से बधाई दी जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में मुंबई भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष वसीम खान ने राजश्री शिरवाडकर को शुभकामनाएं और बधाई दी। इस दौरान वसीम खान के साथ हुसेन पठाण, बशीर खान, शाहनवाज पठाण, सलमान खान, जमीर खान और एंग्लो फर्नांडिस सहित अनेक लोग उपस्थित थे। राजश्री शिरवाडकर को शिक्षण समिति की अध्यक्षा बनाए जाने पर उन्हें बधाई देते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष वसीम खान ने आशा व्यक्त करते हुए कहा है कि मनपा स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में काफी सुधार होगा। जबकि वरिष्ठ भाजपा नेता हुसेन पठाण ने अपने बधाई में कहा कि राजश्री शिरवाडकर झोपड़पट्टी वाले इलाकों में मुंबई मनपा के स्कूलों को अत्याधुनिक तर्ज पर विकसित करेंगी।

मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपी को नायगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार

मीरा भायंदर (उत्तरशक्ति)। नायगांव पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत बिगत 17/02/2026 को 08.00 बजे से 18/02/2026 को लगभग 12:00 बजे तक, एलएनटी कंपनी साइट, मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग, मुंबई वासमारे पुल के पास, वापाने, नायगांव पूर्व, तालुका वसई, जिला पालघर में, शिकायतकर्ता आकाश कौतिक लाहाणे, उम्र 29 वर्ष, व्यवसाय चालक, सीताराम अपार्टमेंट, जुचंद्र, नायगांव पूर्व, तालुका वसई, जिला पालघर ने शिकायत की कि एक अज्ञात चोर ने सहमति के बिना अपने लाभ के लिए सफेद रंग का होंडा कंपनी का स्कूटर नंबर एम.एच. 48 डी.बी. 7821 चुरा लिया, और नायगांव पुलिस स्टेशन अपराध पंजीकरण संख्या 2016/2026 बीएनएस धाराः 303 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने अपराध पहचान शाखा की दो अलग-अलग टीमें गठित की और अपराध की गहन जांच के बाद आरोपियों की पहचान इस प्रकार की गईः पहला मोसिन चुन्ने खान, उम्र 21 वर्ष, निवासी सेक्टर नंबर 15, बस स्टॉप के पीछे, पानी की टंकी के पास, मीरा रोड, तालुका, जिला ठाणे; दुसरा शाहरुख मतीन खान, उम्र 20 वर्ष, निवासी सेक्टर नंबर 15, एमएचएडीए कॉलोनी, मीरा रोड ईस्ट, तालुका, जिला ठाणे; तीसरा हसनन गुलाम खान, उम्र 19 वर्ष, निवासी सेक्टर नंबर 15, बस स्टॉप के पीछे, पानी की टंकी के पास, मीरा रोड, तालुका, जिला ठाणे। इन सभी को मीरा रोड ईस्ट क्षेत्र से हिरासत में लिया गया और जब उनसे अपराध के संबंध में विस्तार से पूछताछ की गई, तो उन्होंने मीरा रोड ईस्ट, उत्तन और दहिसर, मुंबई क्षेत्रों में 4 अपराध करने की बात स्वीकार की। परिणामस्वरूप, कुल 5 मोटरसाइकिलें, जिनकी कीमत 5 करोड़ रुपये है, जब्त की गईं। उसके पास से 2,85,000/- रुपये जब्त किए गए, जिनमें दो बजाज एनएस पल्सर, एक बजाज 160 पल्सर , एक एक्टिवा स्कूटी और एक एक्सेस स्कूटी शामिल हैं। मीरा रोड पुलिस स्टेशन में मोहसिन चुन्ने खान नामक आरोपी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई, निकेत कौशिक, पुलिस आयुक्त, दत्तात्रेय शिंदे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, श्रीमती पौनिमा चौगुले पुलिस उपायुक्त, सर्कल 2 वसई, नवनाथ घोंगरे, सहायक पुलिस आयुक्त वसई डिवीजन, नायगांव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय हजारे, पुलिस निरीक्षक (अपराध) विजय कदम, सपोनी गणेश केकन, पौपानिरी ज्ञानेश्वर असबे, पोहवा शेखर पवार, सचिन ओलेकर, सचिन मोहिते, पी.ओ.एम. चेतन ठाकरे, सचिन खंटल, अमर पवार, जयवंत खांडवी, अशोक पाटिल, पांडुरंग महाले सभी नियुक्त अधिकारी नायगांव पुलिस स्टेशन, पोहवा अमोल बर्डे नियुक्त अधिकारी पी.ओ.ए. कार्यालय, सर्कल नंबर 02 वसई द्वारा किया गया।

प्रसिद्ध भारतीय कॉमेडियन गुरलीन पन्नू और स्वाति सचदेवा ने फेम के साथ मिलकर लॉन्च की सिंगल-यूज फेशियल किट की नई रेंज

मुंबई/पटना। डाबर इंडिया के सबसे भरोसेमंद और अग्रणी फेशियल ब्लीच ब्रांड, फेम ने दो एडवांस्ड सिंगल-यूज फेशियल ट्रीटमेंट किटः नियासिनमाइड ग्लास ग्लो और हयालूरोनिक लूमी ब्राइट लॉन्च करने की घोषणा की है। इस लॉन्च को एक प्रभावशाली और डिजिटल-फर्स्ट कैंपेन का समर्थन प्राप्त है, जिसमें लोकप्रिय भारतीय कॉमेडियन गुरलीन पन्नू और स्वाति सचदेवा शामिल हैं। यह कैंपेन रोमांटिक ब्रेकअप की उदासी को 'सेल्फ-लव' (स्वयं से प्रेम) के जश्न में बदल देता है। इस पूरे विमर्श का केंद्र एक दमदार ब्रांड सच्चाई हैः प्यार का निखार क्षणिक हो सकता है, लेकिन फेम का निखार लंबे समय तक टिकने के लिए बना है। पन्नू और सचदेवा के व्यंग्यात्मक 'ब्रेकअप शिष्टाचार' वाले वायरल वीडियो क्लिप्स के माध्यम से इस अभियान ने देश भर मंय चर्चा बटोरी है। ब्रेकअप के बाद के उस दौर को आधार बनाकर, जब आत्मविश्वास थोड़ा कम हो जाता है, फेम ने स्किनकेयर को केवल एक रूटीन के रूप में नहीं, बल्कि एक 'कमबैक रिचुअल' (आत्मविश्वास वापसी के अनुष्ठान) के रूप में पेश किया है।

द केरल स्टोरी के निर्देशक सुदीप्तो सेन की चरकः फेयर ऑफ फेथ का ट्रेलर रिलीज

मुंबई/पटना। फिल्म चरकः फेयर ऑफ फेथ के निमार्ताओं ने अपनी आगामी लोककथा-आधारित थ्रिलर का प्रभावशाली ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसने अंधविश्वास और तांत्रिक गतिविधियों से जुड़े भयावह सच को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है। द केरल स्टोरी के निर्देशक सुदीप्तो सेन के समर्थन से बनी यह फिल्म 6 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। निर्देशक शीलादित्य मौलिक द्वारा निर्देशित चरकः फेयर ऑफ फेथ भारत के ग्रामीण अंचलों में प्रचलित अंधविश्वास और कठोर अनुष्ठानों की सच्चाई को गहराई से उजागर करती है। ट्रेलर चरक मेला की पृष्ठभूमि में रचा गया है—एक पारंपरिक उत्सव जो गहन आस्था और खतरनाक रस्मों के लिए जाना जाता है। जैसे-जैसे दृश्य आगे बढ़ते हैं, पूरा समुदाय इस पवित्र मेले की तैयारी करता दिखाई देता है, मानो यह उनकी वर्षों पुरानी मनोकामनाओं को पूरा करने की अंतिम उम्मीद हो।

पालघर में योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति पर जोर

पालघर। जिला परिषद पालघर में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस अवसर पर सांसद डॉ. हेमंत सवरा ने कहा कि योजनाओं के निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। चाहे योजनाएं केंद्र सरकार की हों या राज्य सरकार की, उनका प्रभावी क्रियान्वयन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी संबंधित विभाग यदि समन्वय के साथ कार्य करें तो जिले में योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है।

सामूहिक प्रयासों से सभी योजनाएं होंगी सफल : सांसद डॉ. हेमंत सवरा

इस बैठक का आयोजन जिलाधिकारी कार्यालय में किया गया। बैठक में मनरेगा अंतर्गत स्वरोजगार कार्यों, तालुका स्तर पर बांस रोपण, विभागीय क्रियान्वयन व्यवस्था, मोखाडा एवं जव्हार तहसील में रेशम खेती की प्रगति की समीक्षा की गई। सांसद डॉ. सवरा ने निर्देश दिए कि रेशम खेती के सफल मॉडलों का प्रभावी प्रस्तुतिकरण किया जाये, जिससे अन्य किसान भी प्रेरित हो सकें। इसके साथ ही दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा के अंतर्गत ह्यउमेदह्न अभियान, ह्यलखपति दीदीह्न पहल, स्वयं सहायता समूहों को प्रदत्त रिवॉल्विंग फंड व सामुदायिक संसाधन निधि की स्थिति पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ग्राम

सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पूर्ण, अपूर्ण एवं प्रगति पर चल रहे आवासों की समीक्षा की गई। पीएम जनमन आवास प्लस योजना पर भी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई।

कृषि विभाग की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पीएम किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ग्राम पंचायत विकास योजना, जल जीवन मिशन, जलसंरक्षण, पशुसंवर्धन, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत व रिक्त पदों की स्थिति, शिक्षा विभाग की मध्याह्न भोजन योजना एवं समग्र शिक्षा अभियान, कौशल विकास, खनिज प्रतिष्ठान निधि, दिव्यांग सशक्तिकरण, लघु एवं मध्यम उद्योग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा खेलो इंडिया और युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय की योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान विधायक राजेंद्र गावित ने कहा कि बैठकों को औपचारिकता तक सीमित न रखते हुए योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। इस अवसर पर पालकमंत्री एवं राज्य के वन मंत्री गणेश नाईक के करकमलों से जिला परिषद परिसर में सोलर कार शेड पार्किंग एवं दोपहिया सोलर पार्किंग का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। पालकमंत्री ने जिला प्रशासन के कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम का आयोजन जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा द्वारा किया गया। बैठक के सफल आयोजन में संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।इसमें विधायक राजेंद्र गावित, जिलाधिकारी एवं सदस्य सचिव डॉ. इंदुराणी जाखड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे, जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा की परियोजना संचालिका डॉ. रूपाली सातपुते, जव्हार व डहाणू के परियोजना अधिकारी, पालघर, वाडा, विक्रमगड के नगराध्यक्ष तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

भिवंडी में अवैध पोस्टर-बैनर की अब खैर नहीं आयुक्त के आदेश पर साप्ताहिक अभियान शुरू

आचार्य सूरजपाल यादव
भिवंडी (उत्तरशक्ति)। भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका क्षेत्र में अवैध पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स और होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बतादें कि आयुक्त अनमोल सागर के निर्देश पर प्रभाग 1 से 5 में विशेष अभियान चलाकर 42 अवैध पोस्टर और 138 अवैध बैनर हटाए गए, जबकि एक मामले में एफआईआर दर्ज की गई।

आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यह अभियान हर सप्ताह चलेगा। अवैध फलक पर दर्ज नाम, संस्था, राजनीतिक दल, आयोजक, प्रिंटर और प्रायोजक की जिम्मेदारी तय कर महाराष्ट्र संपत्ति विद्रूपीकरण अधिनियम, 1995 के तहत सीधे मामला दर्ज होगा और हटाने का पूरा खर्च संबंधित पार्टी या व्यक्ति से वसूला जाएगा।

वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के 25वें संस्करण का उद्घाटन

मुंबई (उत्तरशक्ति)। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) के वार्षिक प्रमुख मंच, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट (डब्लूएसडीएस) 2026 के रजत जयंती संस्करण का शुभारंभ भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, माननीय श्री भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया। अपने मुख्य संबोधन में, मंत्री ने समानता, लचीलापन और सतत विकास पर टिकी जलवायु महत्वाकांक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। यह आयोजन जलवायु और विकास से जुड़े परिवर्तनकारी कार्यों के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया भर के नेताओं, नीति-निमार्ताओं, उद्योग जगत के दिग्गजों, शोधकताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है। इस अवसर पर टेराजोन में 'हिम-कनेक्ट' और डब्लूएसडीएस आर्काइवल पॉकेटबुक का विमोचन हुआ।

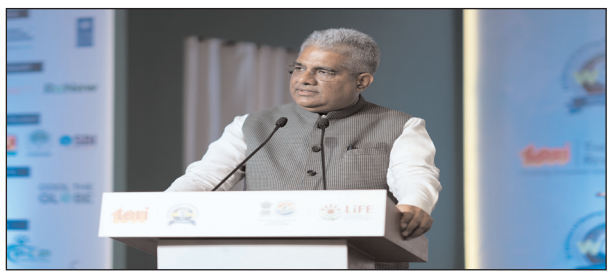

परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन्सः सतत विकास के लिए दृष्टि, स्वर और मूल्य की व्यापक थीम के अंतर्गत आयोजित डब्लूएसडीएस का यह 25वां संस्करण, शिखर सम्मेलन की विरासत में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

यह 'ग्लोबल साउथ' (वैश्विक दक्षिण) में आधारित सतत विकास पर स्वतंत्र रूप से आयोजित होने वाला दुनिया का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय मंच है। स्वागत संबोधन देते हुए टेरी के अध्यक्ष, श्री नितिन देसाई ने कहा, आज दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। हमारे सामने चुनौती जागरूकता की नहीं, बल्कि कार्रवाई की है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का पूरा सफर सिर्फ जागरूकता की बातें करने से हटकर अब इस बात की बेहतर समझ की ओर बढ़ा है कि स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए वास्तव में क्या किया जाना चाहिए। हमारे सामने सबसे गंभीर समस्या जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की है। टेरी की महानिदेशक, डॉ. विभा धवन ने अपने थीम संबोधन में इस बात पर जोर दिया, पिछले 25 संस्करणों के दौरान, डब्लूएसडीएस वैश्विक दक्षिण के लिए जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर विमर्श को दिशा देने वाला एकमात्र स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय मंच बन गया है। हम चर्चाएं तो बहुत कर चुके हैं, लेकिन आज हमें भारत और वैश्विक, दोनों स्तरों पर ठोस कार्रवाई की जरूरत है।

सत्र के समापन से पहले, डॉ. धवन ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा साझा किया गया एक विशेष संदेश पढ़कर सुनाया। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहाः ह्महमारा दृष्टिकोण 'अंत्योदय' से प्रेरित है, जिसका अर्थ है सबसे वंचित व्यक्ति का उत्थान। जलवायु कार्रवाई को सबसे पहले कमजोर, गरीब और वंचित वर्ग की रक्षा करनी चाहिए। ग्लोबल साउथ जलवायु परिवर्तन का असमान रूप से बहुत अधिक भार वहन करता है, फिर भी उनके लिए विकास अनिवार्य है।

दहानू में प्रस्तावित जनाक्रोश मोर्चा व नगरपरिषद घेराव कार्यक्रम स्थगित

पालघर (उत्तरशक्ति)। शुक्रवार 27 फरवरी को दहानू में प्रस्तावित जनाक्रोश मोर्चा एवं दहानू नगरपरिषद के घेराव कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय संगठन की मांगों पर प्रशासन द्वारा सकारात्मक कार्रवाई किये जाने के बाद लिया गया।

उक्त जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन द्वारा संवैधानिक तरीके से रखी गई सभी मांगों को प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है। इनमें से दो प्रमुख मांगों पर तत्काल कार्रवाई भी कर दी गई है, जबकि एक अन्य मांग के संबंध में दहानू नगरपरिषद द्वारा लिखित आश्वासन पत्र प्रदान करते हुए

निर्धारित समयावधि का अनुरोध किया गया है। संगठन की ओर से प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा गया कि पालघर एसपी, सीओ, दहानू नगरपरिषद के अधिकारियों एवं पुलिस निरीक्षक द्वारा सकारात्मक भूमिका निभाई गई, जिसके परिणामस्वरूप आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। संगठन प्रतिनिधि ऋषिकेश मालवीय ने मीडिया को दी जानकारी में बताया कि यदि तय समयसीमा के भीतर शेष मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई तो आगे की रणनीति पर पुनः विचार किया जायेगा। उन्होंने समस्त हिंदू समाज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के सहयोग और एकजुटता के कारण ही यह संभव हो सका।

बी. के. बिड़ला महाविद्यालय में छह दिवसीय हिंदी नवलेखक शिविर

कल्याण (उत्तरशक्ति)। कल्याण में बी. के. बिड़ला महाविद्यालय और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में छह दिवसीय हिंदी नवलेखक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कविता और उपन्यास की रचना प्रक्रिया पर चर्चा हुई।

मुंबई विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हूबनाथ पाण्डेय ने कहा कि कविता लिखने के लिए कवि को एक जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ता है, जो समाज के दर्द को अच्छी तरह महसूस करता है। प्रसिद्ध कथाकार मधु कांकरिया ने उपन्यास की रचना प्रक्रिया पर चर्चा

करते हुए कहा कि हर उपन्यास अपने समय और समाज की आत्मा होता है। इस शिविर में डॉ. नेहा कल्याणी, डॉ. सचिन गपाट, डॉ. रत्नेश मिश्र, और डॉ. बालकवि सुरंजे ने भी अपने विचार रखे। शिविर के संयोजक डॉ. श्यामसुंदर पाण्डेय ने मधु कांकरिया के साहित्य को समाज में अन्याय के विरुद्ध एक नई चेतना जागृत करने वाला बताया। महाविद्यालय के शिक्षा निदेशक डॉ. नरेश चन्द्र, प्राचार्य डॉ. अविनाश पाटील, उप प्राचार्य डॉ. हरीश दुबे, और डॉ. महादेव यादव सहित अन्य सहयोगियों के प्रयासों से यह शिविर सफलतापूर्वक चल रहा है।

रमजान के मद्देनजर महापौर ने जलापूर्ति व स्वच्छता विभाग के कार्यों की समीक्षा के लिए किया विशेष बैठक का आयोजन

आचार्य सूरजपाल यादव
भिवंडी (उत्तरशक्ति)। भिवंडी महानगरपालिका के नवनिर्वाचित महापौर नारायण चौधरी ने अभी औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण नहीं किया है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के पवित्र रमजान माह की शुरूआत को देखते हुए शहर की नागरिक सुविधाओं की समीक्षा के लिए उन्होंने पहल की। महापौर नारायण चौधरी ने पालिका मुख्यालय में आयुक्त अनमोल सागर सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर जलापूर्ति और सार्वजनिक स्वच्छता से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में उपमहापौर तारिक मोमिन, प्रमुख नगरसेवक, जलापूर्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता संदीप पटनावर, सार्वजनिक स्वच्छता विभाग के फैजल तातली सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान नगरसेवकों ने शिकायत की कि कई

क्षेत्रों में अनियमित एवं कम दबाव से पानी की आपूर्ति हो रही है। वहीं रमजान के दौरान स्वच्छता की कमी, समय पर कचरा न उठाए जाने के कारण कई इलाकों में दुर्गंध फैलने की समस्याएं सामने आ रही हैं। इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए महापौर नारायण चौधरी ने जलापूर्ति एवं सार्वजनिक स्वच्छता विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार करने तथा नागरिकों से किसी भी प्रकार की शिकायत न आए, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन को लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकाल के मद्देनजर जल कटौती के कारण पानी की कमी हो सकती है, इसलिए जल वितरण का उचित और पूर्व नियोजन किया जाए। साथ ही उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में काम में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के प्रति कोई नरमी न बरती जाए। आवश्यकता पड़ने पर वे स्वयं स्वच्छता कैबिन में अचानक निरीक्षण कर गैरहाजिर या लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई करेंगे।

महा आवास अभियान में पालघर ने लहराया परचम, लगातार तीन वर्षों से संभाग स्तर पर शानदार प्रदर्शन

पालघर(उत्तरशक्ति/अजीत सिंह)। महा आवास अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना तथा राज्य पुरस्कृत आवास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते पालघर जिले ने वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्ज कर कोकण संभाग में अपनी प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया है। विभिन्न श्रेणियों में संभागीय स्तर पर उल्लेखनीय स्थान प्राप्त कर जिले ने ग्रामीण आवास निर्माण में मिसाल कायम की है। 25 फरवरी को सिडको भवन, बेलापुर, नवी मुंबई स्थित सभागार में आयोजित कोकण संभाग स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में संभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी के हाथों पालघर जिले को सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि पर जिलेभर में खुशी का माहौल है। वर्षवार उपलब्धियों में वर्ष 2021-22 में

प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वश्रेष्ठ जिला परिषद श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया। जब कि राज्य पुरस्कृत आवास योजना में सर्वश्रेष्ठ जिला परिषद श्रेणी में द्वितीय स्थान हासिल किया। वहीं वर्ष 2022-23 में राज्य पुरस्कृत आवास योजना में सर्वश्रेष्ठ जिला परिषद श्रेणी में तृतीय

स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत श्रेणियों में लक्ष्यपूर्ति, गति एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के आधार पर सम्मान मिला तथा रेत उपलब्धता श्रेणी में तहसीलदार, जव्हार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसके बाद वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वश्रेष्ठ जिला परिषद श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया। जब कि पंचायत समिति श्रेणी में विक्रमगड प्रथम, वाडा द्वितीय एवं पालघर तृतीय स्थान पर कब्जा जमाया तथा ग्राम पंचायत श्रेणी में मोज (ता. वाडा) प्रथम एवं खुडेद (ता. विक्रमगड) द्वितीय स्थान पर कब्जा जमाया। राज्य पुरस्कृत आवास योजना में सर्वश्रेष्ठ जिला परिषद श्रेणी में जिला परिषद पालघर ने प्रथम स्थान हासिल किया तथा पंचायत समिति वाडा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे ने कहा कि महा आवास अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण पात्र लाभार्थियों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना संभव हुआ है। जिला परिषद, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के समन्वित प्रयासों से यह सफलता मिली है और भविष्य में भी इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य जारी रहेगा। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भी टीम भावना, सतत समीक्षा और जमीनी स्तर पर प्रभावी समन्वय को इस सफलता का मुख्य आधार बताया। लगातार तीन वर्षों की इस उल्लेखनीय उपलब्धि से कोकण संभाग में पालघर जिले का गौरव और अधिक बढ़ा है। जिला परिषद प्रशासन, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों तथा संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों का सर्वत्र अभिनंदन किया जा रहा है।

उत्तरशक्ति
* संपादकः ओमप्रकाश प्रजापति
* उप संपादकः प्रेम चंद मिश्रा
*प्रबंध संपादकः डा. शेषधर बिन्द
उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।
पत्राचार कार्यालयः
उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)
मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल ऑटाफ हिल वडाला, मुंबई-37
मो.- 9554493941
email ID- uttarshaktinews@gmail.com

स्वामीः शरद फागूराम प्रजापति, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट क्रमांक 4, तल मजला, एन.के. इंडस्ट्रियल स्टेट, आरे रोड, प्रवासी इंडस्ट्रियल एस्टेट, जवल, गेट क्रमांक 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063, महाराष्ट्र से मुदित एवं के-4, रूम नं. 8, ग्राउंड फ्लोर न्यू समता सहकारी को.ऑ. हां. सोसाइटी, एमएमआरडीए कॉलोनी कंजूरमार्ग (वेस्ट), जिला मुंबई- 400078, महाराष्ट्र से प्रकाशित। RNI NO. MAHHIN/2018/76092 * संपादक- ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति, समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के लिए उत्तरदाई तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद मुंबई न्यायालय के अधीन होंगे।
पत्राचार कार्यालयः मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5 ए-337 ट्रैक टर्मिनल, डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल, ऑटाफ हिल, वडाला मुंबई -37, मो.- 9554493941 email ID- uttarshaktinews@gmail.com

पूर्व सांसद उमाकांत यादव एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश

1989 के शस्त्र अधिनियम मामले में चल रही है गवाही

लाइसेंसी बंदूक के नवीनीकरण के दौरान दर्ज हुआ था मुकदमा, अगली सुनवाई 16 मार्च

आजमगढ़ (उत्तरशक्ति)। उमाकांत यादव को गुरुवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट अनुपम त्रिपाठी की अदालत में पेश किया गया। वर्ष 1989 में सरायमीर थाने में उनके विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इस प्रकरण में वर्तमान में गवाही की प्रक्रिया चल रही है। उमाकांत यादव के अधिवक्ता रविंद्र नाथ यादव ने बताया कि वर्ष 1989 में उनके मुवक्किल की बंदूक के लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान पुलिस ने उनके आवास पर तलाशी लेकर लाइसेंसी शस्त्र बरामद किया। उस समय लाइसेंस प्रस्तुत न कर पाने के कारण उनके विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान उमाकांत यादव के गैरहाजिर रहने पर न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। गुरुवार को अदालत में उपस्थित होने पर बचाव पक्ष की ओर से वारंट निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने मामले में गवाही के लिए अगली तिथि 16 मार्च निर्धारित की है। वहीं, गैंगस्टर एक्ट से संबंधित एक अन्य मुकदमे में एमपी-एमएलए सत्र न्यायालय में भी उनकी पेशी हुई, जिसमें अगली सुनवाई की तिथि 12 मार्च नियत की गई है।

डीएम व एसपी ने किया जिला कारागार का औचक निरीक्षण

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिलाधिकारी एंव पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस टीम के साथ संयुक्त रूप से जिला कारागार जौनपुर का औचक निरीक्षण

किया गया। कारागार के अन्दर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर बंदी गृह में बैरक व अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया तथा उनकी सुरक्षा हेतु सम्बंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म करने व सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार

सुजानगंज, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। थाना सुजानगंज पुलिस टीम द्वारा शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म करने व सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने से सम्बन्धित अभियोग में वाँछित एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर, कुँवर अनुपम सिंह द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जौनपुर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी बदलापुर के पर्वेक्षण में थानाध्यक्ष सुजानगंज के नेतृत्व में व0उ0नि0 बृजेश मिश्र मय टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-52/2026 धारा 69/351(2) बीएनएस व 67 आई0टी0एक्ट व 3(2)वी एससी/एसटी एक्ट थाना सुजानगंज जौनपुर में वांछित आरोपीगण कल्याण पटेल पुत्र विजय बहादुर नि0ग्राम नदान थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर को दिनांक 26.02.2026 को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही के उपरांत अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

साइबर टीम ने वापस कराए फ्राड के इक्कीस हजार रुपए

दुद्धी,सोनभद्र (उत्तरशक्ति) पुलिस अधीक्षक द्वारा साइबर अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान एवं अपर पुलिस अधीक्षक (आप.) के दिशा-निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी दुद्धी के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक

थाना दुद्धी एवं थाना स्थानीय के साइबर टीम के द्वारा आवेदक रामलखन पुत्र रामदेव निवासी टेढ़ा थाना दुद्धी के फोन पर अज्ञात नम्बर से कॉल करके डरा धमकार आवेदक के साथ फ्राड कर लेने के सम्बन्ध मे। NCRP पोर्टल पर शिकायत पंजीकृत किया था। पंजीकृत शिकायत में आवश्यक साक्ष्य संकलित कर त्वरित कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित बैंको से पत्राचार किया गया तथा माननीय न्याया० के आदेशानुसार सम्बन्धित बैंक से पत्राचार होल्ड धनराशि 21,000/- आवेदक रामलखन पुत्र रामदेव उपरोक्त को सफलतापूर्वक वापस कराया गया। जिस पर आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक एंव क्षेत्राधिकारी के साथ-साथ प्रभारी निरीक्षक थाना दुद्धी एवं साइबर क्राइम टीम थाना के अधिकारी/कर्मचारीगण की भूरी-भूरी प्रशंसा की गयी।

सिपाही पर पत्नी ने लगाया मारपीट सहित बच्चे को छीनने का आरोप

आजमगढ़ (उत्तरशक्ति)। जनपद के रौनापार थाना क्षेत्र के बनहरा, चॉदपट्टी गांव निवासी सरोज यादव ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर अपने पति सिपाही कृष्ण चन्द गुप्ता पर मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और 10 माह के बच्चे को जबरन छीनने का आरोप लगाया है। प्रार्थिनी के अनुसार, वर्ष 2023 में वह आजमगढ़ स्थित मॉ प्रभावती देवी महिला महाविद्यालय में परीक्षा देने जाती थीं। इसी दौरान उनकी मुलाकात मुबारकपुर थाने में तैनात सिपाही कृष्ण चन्द गुप्ता, निवासी गेंहमौनी, पोस्ट-सिल्लो, थाना-लालगंज, जनपद-बस्ती से हुई। बातचीत के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। महिला का आरोप है कि शादी का प्रस्ताव रखने पर 16 नवम्बर 2023 को नोटेरियल कोर्ट मैरिज की गई। इसके बाद 26 मई 2024 को मुबारकपुर स्थित ताज पैलेस में हिंदू रीति-रिवाज से विधिवत विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद वह ससुराल जनपद बस्ती गईं, जहां सास, ससुर, जेठ और जेठानी द्वारा जाति को लेकर ताने दिए गए और मानसिक उत्पीड़न किया गया। पीड़िता का कहना है कि पति उसे मुबारकपुर में किराए के मकान में लेकर रहने लगे। इसी दौरान वह गर्भवती हुईं। आरोप है कि पति ने गर्भपात का दबाव बनाया, मना करने पर मारपीट और प्रताड़ना शुरू कर दी। महिला का दावा है कि पूर्व में थाने में शिकायत देने पर समझौता कराया गया, लेकिन कोई लिखित कार्रवाई नहीं हुई। बच्चे के जन्म के बाद भी उत्पीड़न जारी रहा। सास द्वारा बच्चे को पति का न बताते हुए विवाद खड़ा किया गया, जिसके बाद कथित रूप से पति ने मारपीट कर 10 माह के बच्चे को अपने पास रख लिया और महिला को घर से निकाल दिया। पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि बच्चे को तत्काल दिलाया जाए तथा पति व ससुराल पक्ष के विरुद्ध उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। पीड़िता के अनुसार पुलिस द्वारा उसे कोर्ट में जाने की सलाह दी गई।

जफराबाद नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि डॉ.सरफराज खान पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला

इम्तियाज अहमद

जफराबाद, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जफराबाद नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि डॉ.सरफराज खान पुत्र गयास-ुद्दीन खान पर दिनांक 25/02/26 दिन बुधवार समय 5 बजे दबंगों ने गोल बनाकर डॉ.सरफराज खान पर उस समय प्राण घातक हमला बोल दिया जब, वह शाम एक कबरिस्तान में मुर्दा दफन करने के मामले में दो पक्षों में विवाद हो रहा था। प्रथम पक्ष आसिफ एवं द्वितीय पक्ष शाहआलम के दरमियान मुर्दा दफन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा था। जिसमे डॉ. सरफराज खान की मध्यस्थता से दोनो पक्ष रजामन्दी से मुर्दा दफन करने के लिए कब्र खोदने के लिये तैयार हो गये। इसी दौरान शाह शब्बीर पुत्र महमूद साकिन शेखवाडा (हिसार कोट) डॉ.सरफराज खान को मां-बहन की गाली देने लगा और अपने सहयोगी साहिल पुत्र रफीक, हशमत पुत्र अफसर एवं बिलाल पुत्र

अफसर ने डॉ.सरफराज खान पर हमला बोल दिया। हमले में डॉ.सरफराज खान के ऊपर हाथ-पैर इटा-पत्थर चलाने लगे जिसके कारण डॉ.साहब के चेहरे पर चोट आयी उक्त वारदात में दाऊद पुर महफूज भीड़ मे लोगो को उकसाकर मौहोल खराब करने की कोशिश कर रहा था। पूर्व इसके द्वारा डॉ साहब के ऊपर कई बार हमला एवं वदतमीजी की जा चुकी है। डॉ.साहब ने थाना अध्यक्ष जफराबाद को इस प्रकरण की लिखित में तहरीर दी, पुलिस तत्काल हरकत में आ गई। वही पुलिस ने पांच नामजद लोगों के खिलाफ इठर की गंभीर धारा 12191(2) 115(2) 352, 125(ए), 131 ग मुकदमा दर्ज कर, आगे की विधि करवाई में जुट गई। खबर लिखे जाने तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई थी।वही डॉ.सरफराज खान का कहना था कि मेरी जान माल का खतरा बना हुआ है। अगर प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं की गयी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है।

टिकट से पहले ही घिरे भावी प्रत्याशी, पुश्तैनी जमीन बिक्री पर परिवार में विवाद

विशाल सोनी

शाहगंज,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। विधान सभा मे बैठने को लेकर कई वर्षों से सपना देख रहे एक बड़े पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपने आपको परोसने वाले नेता जी चुनाव से पहले ही घरेलू कलह में उलझते जा रहे है।

सूत्रों की माने तो भारी भरकम सम्पत्ति और कारोबारी नेता जी की एक पुरखो की करोड़ो की जमीन को उनके ही घर के एक सदस्य परिवार के सदस्यों की अनुमति के बिना ही उक्त जमीन को भेज दी गयी। जिसकी कीमत करोड़ो में बताई जा रही है।जमीन बेचने की खबर जैसे ही परिवार के अन्य सदस्यों को हुई तो कलह मचना लाजमी था।शो हुआ भी।अब बेचारे नेता जी फंस गए मझदार में।चचाओं में लोग चटकारे लेते हुए कहने लगे की जब नेता जी अपने परिवार की समस्याओं का निवारण नही कर पा रहे हैं तो विधान सभा क्षेत्र के जनता के समस्याओं कैसे निवारण करेंगे।

बताते चले उक्त नेता जी बीते 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बहुत हाथ पैर मारे मगर दाल नही गल सकी। अब 2027 के विधानसभा चुनाव में नेता जी कोई कोर कसर नही छोड़ना चाहते।इसी क्रम में नेता जी का रूठे को मनाना, माने हुए को और मजबूत करना, ब्राह्मण और छत्रिय मतदाताओं को रिझाने के लिए अभी से अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिये हैं।और तो और अल्पसंख्यक मतदाताओं को पहले से अपना मान कर बैठे हैं। मगर शायद नेता जी नही जानते की यह जनता है सब जानती है। फिलहाल आगे यह देखना है दिलचस्प होता है की इस बार नेता जी चुनाव लड़ पाते है।या इस बार भी दिल के अरमां आंसुओं में बह जाते हैं।

वरासत दर्ज करने के नाम पर लेखपाल का 'खेल', सही आवेदनों को भी बताया विवादित

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। तहसील सदर के अंतर्गत ग्राम विजय मंदिर उर्फ प्रेमराजपुर में राजस्व विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित निखलेश बिन्द ने जिलाधिकारी को साक्ष्यों के साथ प्रार्थना पत्र सौंपकर लेखपाल पर भ्रष्टाचार और गलत रिपोर्ट लगाने का आरोप लगाया है।

दस्तावेज सही, फिर भी रिपोर्ट 'असहमत': ताजा दस्तावेजों के अनुसार, कन्हैया लाल बिन्द के वारिसों के रूप में कमलेश कुमार (31 वर्ष) और निखलेश बिन्द (28 वर्ष) का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया गया था। यह मामला गाटा संख्या 330मि, 332/2, 332मि और 337मि से जुड़ा है। नियमों के अनुसार, पिता की मृत्यु के बाद बेटों का नाम वरासत के रूप में दर्ज होना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन लेखपाल की रिपोर्ट में जानबूझकर वारिसों के आगे 'असहमत दर्ज कर दिया गया है। लेखपाल पर अवैध मांग का आरोपनिखलेश का आरोप है कि लेखपाल विनय दुबे ने वरासत दर्ज करने के बदले अनुचित लाभ की मांग की थी। मांग पूरी न होने पर लेखपाल ने अपनी जांच आख्या में मामले को 'विवादित श्रेणी में डाल दिया। पोर्टल के स्टेटस में साफ दिख रहा है कि लेखपाल की जांच आख्या में बिना किसी ठोस कारण के इसे विवादित दिखाया गया है, जिससे वारिसों का हक मारा जा रहा है। पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है कि लेखपाल द्वारा लगाई गई गलत 'विवादित रिपोर्ट को निरस्त किया जाए। गाटा संख्या 330, 332 और 337 पर वारिसों के नाम दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी की जाए। पद का दुरुपयोग करने वाले संबंधित लेखपाल के खिलाफ विभागीय जांच कर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले ने एक बार फिर राजस्व विभाग में निचले स्तर पर फैले भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है, जहाँ सही वारिसों को भी अपने हक के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

अखिलेश यादव पर सवाल सुनते ही रामभद्राचार्य ने बंद किया गाड़ी का शीशा

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। विश्वविख्यात संत एवं रामकथा मर्मज्ञ रामभद्राचार्य गुरुवार को जौनपुर पहुंचे। वे हेलिकॉप्टर से यहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। आगमन पर उन्होंने नगर स्थित प्रसिद्ध मां शीतला माता मंदिर में दर्शन-पूजन कर मत्था टेका।

मंदिर परिसर में उनके पहुंचने की सूचना मिलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दर्शन के बाद जब वे अपने वाहन की ओर बढ़े तो पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हालिया बयान को लेकर सवाल किया। सवाल सुनते ही उन्होंने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए तत्काल अपनी गाड़ी का शीशा बंद कर लिया और आगे बढ़ गए। इस घटनाक्रम को लेकर मौके पर मौजूद लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। इसके बाद वे निर्धारित निजी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां आयोजकों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जौनपुर उनकी जन्मभूमि है और यहां आकर उन्हें आत्मिक शांति एवं विशेष आनंद की अनुभूति होती है। उनके आगमन को लेकर समर्थकों में उत्साह का माहौल रहा, जबकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन भी सतर्क दिखा।

शोधार्थी के लिए नवाचार सबसे बड़ी पूंजी: कुलपति

डिजिटल युग में आईपीआर अत्यंत महत्वपूर्ण: अशोक सहगल

नवाचार संरक्षण राष्ट्र की प्रगति के लिए जरूरी: आलोक मिश्रा

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में गुरुवार को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट (आईपीआर) सेल की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय बौद्धिक संपदा अधिकार : उभरती प्रवृत्तियाँ और चुनौतियाँ रहा। इस अवसर पर अपने आशीर्वचन में कुलपति प्रो.वंदना सिंह ने कहा कि इन्वेंशन ही एसेट है। किसी भी संस्थान अथवा शोधकर्ता के लिए नवाचार उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। यदि नए विचारों, शोध कार्यों और आविष्कारों को सही दिशा में संरक्षित किया जाए तो वही आर्थिक उन्नति और सामाजिक विकास का मजबूत आधार बनते हैं। विश्वविद्यालयों को नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े नियमों, पेटेंट प्रक्रिया और कानूनी प्रावधानों की सही जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही डिजिटल युग की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज कॉपीराइट उल्लंघन, डेटा सुरक्षा और ऑनलाइन सामग्री की सुरक्षा गंभीर विषय बन चुके हैं।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक सहगल ने कहा कि डिजिटल युग में बौद्धिक संपदा अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। यदि सृजनकर्ता जागरूक नहीं रहेगा तो उसके नवाचार, शोध एवं रचनात्मक कार्य का दुरुपयोग हो सकता है। उन्होंने पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि के पंजीकरण की विधि को विस्तार से समझाते हुए समयबद्ध फाइलिंग की आवश्यकता पर बल दिया।

भारतीय पेटेंट कार्यालय, नई दिल्ली के सहायक नियंत्रक (पेटेंट एवं डिजाइन) आलोक मिश्रा ने कहा कि नवाचार को संरक्षित करना राष्ट्र की प्रगति के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि देश को विकसित करने के लिए आईपीआर

सेक्टर को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने पेटेंट आवेदन की प्रक्रिया, परीक्षा प्रणाली तथा स्टार्टअप एवं शैक्षणिक संस्थानों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी।

कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान (के.एन.आई.टी.) सुल्तानपुर के एसोसिएट प्रोफेसर प्रो. प्रदीप कुमार ने कहा कि तकनीकी संस्थानों में शोध को उद्योग से जोड़ते समय आईपीआर की समझ आवश्यक है। इससे शोध का व्यावसायीकरण संभव होता है और नवाचार को उचित पहचान मिलती है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विधि संकाय के डॉ. अभिषेक कुमार ने कहा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में बौद्धिक संपदा अधिकार आर्थिक विकास का प्रमुख आधार बन चुका है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समझौतों और भारतीय कानूनों के समन्वय पर प्रकाश डाला।

टी.डी. लॉ कॉलेज, जौनपुर के डॉ. यशवंत सिंह ने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकार कानून और नवाचार के बीच सेतु का कार्य करता है। विधि के विद्यार्थियों को आईपीआर के बदलते स्वरूप और न्यायिक दृष्टिकोण की जानकारी होना समय की मांग है। इसके पूर्व आईपीआर सेल के नोडल अधिकारी प्रो. रविप्रकाश ने स्वागत भाषण कर कार्यशाला की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। समापन सत्र में परीक्षा नियंत्रक डॉ विनोद कुमार सिंह ने कहा कि डिजीटल युग में अपने हर शोध हो या सृजन उसके प्रति सजग रहने की जरूरत है। इसी के तहत हर संस्थाओं में आपीआर सेल का गठन हो रहा है। संचालन डॉ. रसिकेश और धन्यवाद ज्ञापन प्रो. प्रदीप कुमार ने किया।

कार्यक्रम में प्रो. प्रमोद कुमार यादव, प्रो. राजेश शर्मा, प्रो. विनोद कुमार, प्रो. प्रमोद कुमार, डॉ. सुनील कुमार, डॉ. मंगला प्रसाद यादव, डॉ. नीतेश जायसवाल, डॉ. प्रवीण कुमार सिंह, डॉ. नीरज अवस्थी, डॉ. जया शुक्ला, डॉ. नृपेन्द्र सिंह, पूनम सोनकर, डॉ. ज्योति सिंह, डॉ. अजय कुमार मौर्य, डॉ. सुधीर सिंह, डॉ. शैलेश प्रजापति, रीतेश बरनवाल, सहित अनेक शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

राजकीय आईटीआई सिद्दीकपुर में वृहद रोजगार मेला

28 फरवरी को, 60 से अधिक कंपनियां करेंगी शिरकत

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। शासन की मंशा के क्रम में एवं जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र के निदेर्शानुसार जनपद के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक 28 फरवरी 2026 को राजकीय आई०टी०आई० सिद्दीकपुर परिसर में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश-विदेश की 60 बहुप्रतिष्ठित कम्पनियों 1000 से अधिक पदों पर 12 हजार से 35 हजार तक प्रतिमाह वेतन के अवसर के साथ प्रतिभाग कर रही है।

योग्यताधारी अभ्यर्थियों को मेले में प्रतिभाग करने के लिए आयुसीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता के रूप में कक्षा 10वीं, 12वीं उर्तीण तथा स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा आई०टी० आई०, फामेर्सी या अन्य उच्चतर डिग्री धारक अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए रोजगार संगम पोर्टल (rojgaarsangam.up.gov.in) पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराते हुए मेले में निजी क्षेत्र की कम्पनियों में साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, अतः अभ्यर्थी उक्त पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर मेले में प्रतिभाग करें अभ्यर्थी अपने साथ शौक्षिक अभिलेखों की मूल प्रति और छायाप्रति अवश्य लेकर पहुंचें।

जिलाधिकारी ने किया भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जनपद में आमजन को वित्तीय समावेशन से सम्बन्धित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉ.दिनेश चंद्र द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आदि के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में से एक है, अतः इस योजना के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों की पात्रता की जांच करते हुए अधिक से अधिक आवेदन स्वीकृत कराए जाएं, जिससे युवा अपना स्वयं का उद्यम शुरू कर सके और आत्मनिर्भर बन सके।

उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए तथा किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न की जाए।

जिलाधिकारी ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के अंतर्गत लंबित ऋण आवेदनों के शीघ्र निस्तारण तथा युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने

हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के प्रति अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए, जिससे लोगो को इन योजनाओं का लाभ मिल सके।

उन्होंने बैंक परिसर में व्यवस्थाओं, एवं ग्राहक सुविधाओं का भी अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर संबंधित बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

जहर देकर हत्या करने वाले गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार

आजमगढ़(उत्तरशक्ति)। थाना अहरौला क्षेत्र में जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या के एक गंभीर मामले में सक्रिय संगठित गिरोह के दो वांछित अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह गिरोह गैंग लीडर श्रवण पाण्डेय पुत्र रामसकल पाण्डेय, निवासी ग्राम भोगईचा, थाना अहरौला के नेतृत्व में संचालित था, जो अपने साथियों के साथ मिलकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ के उद्देश्य से जघन्य अपराधों को अंजाम देता था। पुलिस के अनुसार, 16 मार्च 2025 को शाम भोगईचा निवासी सुनील पाण्डेय पुत्र रामकृपाल को बाजार जाते समय अभियुक्तों ने पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें अपने घर के अंदर ले जाकर मारपीट की गई और जबरन जहरीला पदार्थ खिलाया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना के संबंध में 17 मार्च 2025 को मृतक की पत्नी अंजनी पाण्डेय की तहरीर पर थाना अहरौला में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी गिरफ्तारी के क्रम में गुरुवार को थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा ने पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर ग्राम भोगईचा स्थित जेठू सिंह स्मृति द्वार मोड़ से दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में रामसकल पाण्डेय पुत्र स्वर्गीय राजाराम पाण्डेय और रवि पाण्डेय पुत्र रामसकल पाण्डेय शामिल हैं। दोनों ग्राम भोगईचा, थाना अहरौला के निवासी हैं।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आधार संतृप्तिकरण संबंधी हुई बैठक

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। नया आधार पंजीकरण (सभी आयु वर्ग) पूर्णतः निःशुल्क है। 5 से 7 वर्ष एवं 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य अपडेट भी निःशुल्क रखा गया है। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आधार संतृप्तिकरण के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद में जिलाधिकारी के द्वारा आधार नामांकन एवं अपडेट की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का आधार नामांकन अपेक्षाकृत कम है, जिस पर जिलाधिकारी ने विशेष ध्यान देते हुए शिविर आयोजित कर शत-प्रतिशत आधार कवरेज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान UIDAI द्वारा निर्धारित आधार सेवा शुल्क की जानकारी भी प्रस्तुत की गई। बताया गया कि नया आधार पंजीकरण (सभी आयु वर्ग) पूर्णतः निःशुल्क है। 5 से 7 वर्ष एवं 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य अपडेट भी निःशुल्क रखा गया है। बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट, आइरिस एवं फोटोग्राफ) हेतु रू.125 तथा जनसांख्यिकीय विवरण (नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल, लिंग) में संशोधन हेतु रू.75 शुल्क निर्धारित है। ऑनलाइन माध्यम से दस्तावेज अपडेट निर्धारित अवधि तक निःशुल्क उपलब्ध है, जबकि पीवीसी आधार कार्ड हेतु रू.75 एवं आधार प्रिंट (अ4 साइज) के लिए रू.40 शुल्क निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी संबंधित विभाग आधार नामांकन एवं अपडेट कार्यों में तेजी लाएं तथा पात्र लाभार्थियों को शत-प्रतिशत रूप से आच्छादित करें। साथ ही आमजन को जागरूक करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि न ली जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 परमानंद झा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉ0 अरुण कुमार यादव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

जनपद के किसानों एवं एफपीओ को तिरपाल, कृषि यंत्र तथा फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों के क्रय पर मिलेगा अनुदान

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। उप कृषि निदेशक जौनपुर ने अवगत कराया है कि जनपद में विभागीय पोर्टल agridarshan.up.gov.in पर पंजीकृत एफ०पी०ओ० एवं कृषकों को सूचित किया जाता है कि कृषि विभाग द्वारा जनपद जौनपुर में संचालित केन्द्र पुरोनिधानित नेशनल मिशन ऑन एडिबिल ऑयल (आयलसीड्स) योजनान्तर्गत मिनी आयल एक्सट्रैक्शन यूनिट, ऑयल एक्ट्रेक्शन यूनिट (10 टन क्षमता), तिरपाल तथा सब मिशन ऑन एग्री लचर नैकेनाइजेशन योजनान्तर्गत एकल कृषि यंत्र एवं प्रमोशन ऑफ मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेण्ट ऑफ क्राप रेज्ड्यू योजनान्तर्गत फसल अवशेष प्रबन्धन के यंत्रों के क्रय एवं स्थापना पर अधिकतम अनुमन्य अनुदान डी०बी०टी० के माध्यम से दिये जाने का प्राविधान है। उक्त के क्रम में शासन के निदेर्शानुसार विभागीय पोर्टल https://agridarshan.up.gov.in मिनी आयल एक्सट्रैक्शन यूनिट एवं ऑयल एक्ट्रेक्शन यूनिट (10 टन क्षमता) की बुकिंग हेतु दिनांक 10.03.2026 एवं अन्य कृषि यंत्रों की बुकिंग हेतु 04.03.2026 तक बुकिंग के लिये पोर्टल खुला है। अनुदान प्राप्त करने हेतु इच्छुक एफ०पी०ओ० एवं इच्छुक कृषक उक्त पोर्टल के माध्यम से आनलाइन निर्धारित टोकन धनराशि जमा करते हुए टोकन जनरेट करके अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते है।

अन्ना का 'अनशन' रंग लाया: जिलाधिकारी ने माना जायज हैं मांगें

जौनपुर। जनपद जौनपुर कलेक्ट्रेट में भ्रष्टाचार और लचर राजस्व प्रणाली के खिलाफ समाजसेवी जज सिंह अन्ना का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन आखिरकार रंग लाया। 26 फरवरी गुरुवार शाम 4:40 बजे जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र सिंह के ठोस आश्वासन के बाद अन्ना ने अपना अनशन समाप्त किया। अनशन की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने जज सिंह अन्ना को अपने कार्यालय में बुलाया और संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में लंबी वार्ता की। जिलाधिकारी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि अन्ना की मांगें पूरी तरह जायज हैं। उन्होंने कड़े लहजे में अधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्षों से लंबित बैनामा और कब्जे के मुकदमों पर अब 'तारीख पे तारीख' नहीं चलेगी जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र सिंह ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जिले की तहसीलों में बैनामा के जितने भी पेंडिंग मुकदमे हैं, उन सभी का सामूहिक अभियान चलाकर निपटारा किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार और लेटलतीफी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। अनशन समाप्त करने के बाद जज सिंह अन्ना ने कहा कि यह सिर्फ उनकी जीत नहीं बल्कि उन हजारों पीड़ितों की जीत है जो दशकों से तहसीलों में न्याय के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं प्रशासन के आश्वासन पर अनशन तोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी नजर कार्यवाही की रफ्तार पर बनी रहेगी।

अग्नि को साक्षी मान एक दूजे के हुए अतुल व निधि

बनारसी आभा में सजा वैवाहिक उत्सव, आशीर्वाद से आलोकित हुआ नवदंपति का जीवन

-सुरेश गांधी

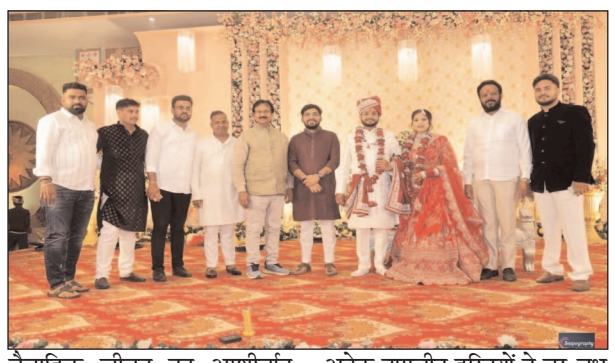

वाराणसी. काशी की सांस्कृतिक परंपरा, संगीत और आत्मीयता से सराबोर एक भव्य वैवाहिक समारोह में अतुल उमरवैश्य पुत्र अनुसूईया उमरवैश्य का विवाह निधि पुत्री सीता मुकेश चंद उमरवैश्य के साथ अत्यंत हर्षोल्लास और वैदिक रीति-विधान के साथ संपन्न हुआ। ऐतिहासिक परिवेश से सुसज्जित वाराणसी किला परिसर में आयोजित इस समारोह ने पारंपरिक बनारसी वैभव और आधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम को साकार कर दिया।

जयमाला के पावन अवसर पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उनकी धर्मपत्नी लता एकशिंदे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवविवाहित जोड़े को सुखमय वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। दूर रहकर भी उनके स्नेह और शुभकामनाओं की उपस्थिति ने समारोह की गरिमा को और अधिक बढ़ा दिया। बता दें, दोनों अतिथियों का विवाह समारोह में आना था, लेकिन कुछ कारणों से एनवक्त पर उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया. अतुल एकनाथ शिंदे के पारीवारिक पीआरओं हैं. उनका गहजनपद प्रतापगढ़ है, लेकिन वे मुंबई में ही शिंदे के परिवार का मैनेजमेंट देखते हैं.

समारोह में विभिन्न राज्यों से आए जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों, विधायकों, नगर सेवकों तथा सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की अनेक नामचीन हस्तियों ने वर-वधू को आशीष प्रदान किया। पारिवारिक आत्मीयता और सामाजिक सहभागिता का यह समागम काशी की जीवंत परंपरा का सुंदर उदाहरण बनकर उभरा। बनारसी आभा से सजे इस विवाह समारोह का वातावरण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो काशी की आध्यात्मिक आत्मा स्वयं इस शुभ रात्रि को अपनी मधुरता से आलोकित कर रही हो। दूल्हा-दुल्हन के चेहरे पर झलकती प्रसन्नता, परिवारजनों का उल्लास और अतिथियों की रौनक ने पूरे आयोजन को अविस्मरणीय बना दिया। बारात के आगमन के साथ ही उत्सव अपने चरम पर पहुंच गया। शहनाई की मधुर धुनें और बैंड-बाजों की गूंज ने काशी की संगीत परंपरा को जीवंत कर दिया। पारंपरिक बनारसी पगड़ी, शेरवानी और सांस्कृतिक परिधानों में सजे युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई उत्सव की लय में थिरकता नजर आया। यह दृश्य केवल एक विवाह नहीं, बल्कि संस्कृति और संबंधों का उत्सव प्रतीत हो रहा था।

समारोह की भव्यता और आकर्षण का प्रभाव सोशल मीडिया पर भी स्पष्ट दिखाई दिया। विवाह की झलकियां तेजी से फेसबुक, वाट्स्प, ट्वीटर सहित सोशल मीडिया पर साझा की जाने लगीं। तस्वीरों और वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और नवदंपति के उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाएं दीं। काशी की परंपरा, आधुनिक तकनीक और सामाजिक आत्मीयता के संगम से सजा यह वैवाहिक समारोह इस बात का प्रतीक बना कि भारतीय संस्कृति में विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों और सामाजिक संबंधों का पवित्र उत्सव होता हैकृजिसमें आशीर्वाद, परंपरा और आनंद की निरंतर धारा बहती रहती है।

फांसी लगाकर आत्महत्या करने का असफल प्रयास

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। घर के अंदर गले में फांसी लगाकर आत्महत्या करने के प्रयास में युवक की हालत बिगड़ गई। उसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के गिरधरपुर गांव निवासी रिजवान उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र इजरायल गुरुवार तीसरे पहर घर के अंदर किसी बात से नाराज होकर गले में फांसी का फंदा लगाकर झूल गया। यह तो अच्छा हुआ कि परिजनों की निगाह पड़ गई। तुरंत परिजन दौड़ पड़े और उसे नीचे उतारे लेकिन तब तक उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचा कर भर्ती करवाया।

दो महिलाओं ने विषाक्त का सेवन कर जान देने का किया प्रयास

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। दो विवाहिताओं ने कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया। जिससे उनकी हालत बिगड़ गई दोनों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि जफराबाद थाना क्षेत्र के सदलीपुर गांव निवासी फरीदा उम्र लगभग 22 वर्ष पत्नी दिलशाद ने बुधवार रात्रि पारिवारिक कलह से तंग आकर सिंदूर पीकर जान देने का प्रयास किया जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। इसी प्रकार इसी थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी आसिया उम्र लगभग 28 वर्ष पत्नी स्वर्गीय नदीम ने परिजन से हुई किसी बात को लेकर नाराज होकर विषाक्त का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया। जिससे उसकी हालत खराब हो गई। दोनों के परिजनों ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचा कर भर्ती कराया।

आधार संतृप्तिकरण संबंधी बैठक संपन्न

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आधार संतृप्तिकरण के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद में जिलाधिकारी के द्वारा आधार नामांकन एवं अपडेट की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का आधार नामांकन अपेक्षाकृत कम है, जिस पर जिलाधिकारी ने विशेष ध्यान देते हुए शिविर आयोजित कर शत-प्रतिशत आधार कवरेज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान UIDAI द्वारा निर्धारित आधार सेवा शुल्क की जानकारी भी प्रस्तुत की गई।

राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर समारोह सम्पन्न

सेवानिवृत्त जिला जज विनोद कुमार मिश्रा रहे मुख्य अतिथि

जौनपुर। सावित्री केवला शंकर विधि महाविद्यालय, दतॉव (जौनपुर) में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) के विशेष शिविर का समापन समारोह गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार के सेवानिवृत्त जिला जज एवं जौनपुर निवासी विनोद कुमार मिश्रा रहे। उनके आगमन पर महाविद्यालय परिवार द्वारा माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता महाविद्यालय के स्वामी एवं संरक्षक प्रेम तिवारी ने की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास का सशक्त माध्यम है। उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान स्वयंसेवकों ने स्वच्छता अभियान, जनजागरूकता रैली, सामाजिक सेवा एवं ग्रामीण संपर्क जैसे अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्होंने महाविद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह संस्थान गुणवत्तापूर्ण विधि शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक मूल्यों के संवर्धन के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। मुख्य अतिथि विनोद कुमार मिश्रा ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना है। उन्होंने स्वयंसेवकों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविर युवाओं में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और सेवा भावना का विकास करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे न्याय, नैतिकता और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। कार्यक्रम के दौरान शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्वयंसेवकों को सम्मानित भी किया गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। समारोह में महाविद्यालय के प्राध्यापकगण, छात्र-छात्राएं एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

स्नेहा दुबे पंडित ने राज्यपाल के भाषण का किया समर्थन

वसई रोड। स्नेहा दुबे पंडित ने विधानसभा में राज्यपाल के भाषण का समर्थन करते हुए राज्य सरकार के विकास कार्यों की सराहना की और वसई व पालघर जिलों की विभिन्न लंबित मांगों को सदन में उठाया।उन्होंने वर्ष 2024-25 में 1.64 लाख करोड़ रुपये के विदेशी निवेश, 91 हजार करोड़ रुपये के एफडीआई और 30 हजार करोड़ रुपये के एमओयू के लिए सरकार को बधाई दी।मुख्य मांगें और मुद्दों में वसई-विरार क्षेत्र की 25,000 लघु व मध्यम उद्योगों के लिए मौजूदा दर पर लीज बढ़ाने की नीति लागू करने की मांग।औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, सीवेज, वेस्ट मैनेजमेंट और निर्बाध बिजली आपूर्ति हेतु विशेष फंड।पोमन, मालजीपाड़ा और नायगांव में स्टूडियो सेक्टर के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं।वसई में MIDC की स्थापना और महिलाओं के लिए अलग ITI शुरू करने की मांग।पालघर में बांस उद्योग नीति के तहत रोजगार गारंटी/उरफ फंड तथा शबरी आदिवासी घरकुल योजना लागू करने की मांग। वसई-विरार को चौथी मुंबई बनाने हेतु सड़क कनेक्टिविटी के लिए त्वरित फंड। वसई में पाचू पोर्ट, शिपबिल्डिंग यार्ड और मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। वसई किले को UNESCO विश्व धरोहर सूची में शामिल करने और उसके जीर्णोद्धार के लिए फंड। वसई में आधुनिक क्रिकेट अकादमी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मांग शामिल रही।अंत में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का विकास सामूहिक संकल्प से ही संभव है।

दिल्ली के वरिष्ठ कवि डॉ ओंकारनाथ त्रिपाठी का मुंबई में भव्य स्वागत

-प्रोफेसर डॉ दयानंद तिवारी

मुंबई (उत्तरशक्ति)। काव्यसृजन न्यास एवं अखिल भारतीय काव्य मंच के संयुक्त तत्वावधान में दिल्ली से पधारे वरिष्ठ कवि डॉ ओंकारनाथ त्रिपाठी के सम्मान में सांताक्रुज ईस्ट, मुंबई स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद हॉल में एक गरिमामय एवं भव्य काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आ. हौसिला प्रसाद अन्वेषी ने की तथा संचालन आ. ओमप्रकाश तिवारी ने प्रभावशाली ढंग से किया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉ ओंकारनाथ त्रिपाठी मंचासीन रहे। विशिष्ट अतिथियों में प्रो. डॉ दयानंद तिवारी, निडर जौनपुरी एवं सौ. कुसुम तिवारी झल्ली की उपस्थिति से मंच की शोभा बढ़ी। संस्था द्वारा सभी अतिथियों का अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया गया।

अपने उद्बोधन में प्रो. डॉ दयानंद तिवारी ने कहा कि डॉ ओंकारनाथ त्रिपाठी आज राष्ट्रीय ख्याति के कवि के रूप में स्थापित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ओंकार की काव्य साधना, वैचारिक गहराई और राष्ट्रभाव से ओतप्रोत रचनाएँ उन्हें देशभर में विशिष्ट पहचान दिला रही हैं। डॉ तिवारी ने आगे कहा कि ऐसे रचनाकार केवल साहित्य नहीं रचते, बल्कि समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं। मुंबई में उनका यह सम्मान समस्त साहित्य प्रेमियों के लिए गौरव का विषय है।

सरस्वती वंदना के पश्चात आयोजित काव्य पाठ में वरिष्ठ एवं युवा कवियों ने अपनी विविध रचनाओं से उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अध्यक्ष महोदय ने सभी रचनाकारों की सारगर्भित समीक्षा करते हुए उनके साहित्यिक योगदान की सराहना की।

मां की पुण्यतिथि पर समाजसेवी विनोद सिंह ने जरूरतमंद महिलाओं को बांटी साड़ी

जौनपुर। मां का स्थान स्वर्ग से भी बड़ा माना गया है, यही कारण है कि मां को भगवान का दर्जा दिया गया है। मुंबई के युवा समाजसेवी तथा केडीआर फाउंडेशन के निर्देशक विनोद सिंह और उनके भाइयों अमरधारी सिंह, अशोक सिंह व विनय सिंह ने अपनी मां श्रीमती केवला देवी रामबहाल सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर सैकड़ो जरूरतमंद महिलाओं को साड़ी का वितरण किया। जनपद के बदलापुर तहसील अंतर्गत स्थित कठार गांव के केडीआर हाउस में भजन संध्या एवं श्रद्धांजलि सभा के बीच आयोजित कार्यक्रम में जरूरतमंद महिलाओं को साड़ियों का वितरण किया गया। इस अवसर पर सिंगरामऊ रियासत के कुंवर जयसिंह, भाजपा युवा नेता अखिल मिश्रा, बदलापुर नगरपालिका अध्यक्ष वैभव सिंह, वरिष्ठ पत्रकार शिवपूजन पांडे, सत्येंद्र सिंह घोड़ा वाला, रामधारी सिंह, सुभाष सिंह, प्रमोद शुक्ला, त्रिभुवन सिंह, राजेश सिंह, विशाल सिंह, विकास सिंह, सौरभ सिंह, शिवम सिंह समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह को आना था, परंतु एक आवश्यक मीटिंग में शामिल होने की सूचना मिलते ही उन्हें मुंबई वापस जाने के लिए लौटना पड़ा। उन्होंने अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कहा कि मां के आशीर्वाद से ही बच्चे विकास करते हैं। अंत में अमरधारी सिंह ने अपने परिवार की तरफ से समस्त लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया।

डॉ. हेमंत सावरा ने वाडा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा

पालघर। डॉ. हेमंत सावरा ने वाडा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की आयोजित बैठक में भाग लेकर उद्यमियों के साथ विस्तृत चर्चा की। इस बैठक में औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक और ठोस संवाद हुआ। बैठक के दौरान वाडा-कुडूस और अंबाडी सड़कों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण, टएइ पावर सप्लाई से संबंधित समस्याएं, बढ़ते ट्रैफिक जाम और उसके प्रभावी समाधान सहित इंडस्ट्रियल सेक्टर के अन्य लंबित आवश्यक मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।डॉ. सावरा ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र स्थानीय विकास की रीढ़ है। उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आश्वासन दिया कि संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र ठोस निर्णय लिए जाएंगे।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि और वाडा तालुका के समग्र विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में उपस्थित उद्यमियों ने भी अपने सुझाव और समस्याएं खुलकर रखीं, जिस पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया गया।

मुलुंड पश्चिम में पुलिस कार्रवाई के विरोध में फेरीवालों का प्रदर्शन

मुंबई। मुलुंड पश्चिम में जे.एन. रोड पर पुलिस द्वारा फेरीवालों को धंधा न लगाने देने के विरोध में पात्र फेरीवालों ने अनोखा प्रदर्शन किया। आक्रोशित फेरीवालों ने अपने फल और सब्जियां सड़क पर फेंककर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी जताई। फेरीवालों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से जे.एन. रोड पर उन्हें बैठने से रोका जा रहा है, जबकि पूरे मुलुंड परिसर की अन्य सड़कों पर फेरीवाले नियमित रूप से अपना व्यवसाय कर रहे हैं। उनका कहना है कि संबंधित स्थान ह्नो हॉकिंग जोनह्व घोषित नहीं है, फिर भी केवल इसी सड़क पर सख्ती बरती जा रही है। प्रदर्शन कर रहे विक्रेताओं ने बताया कि उनके पास वैध कागजात मौजूद हैं और वे नियमों के तहत व्यवसाय कर रहे हैं। कुछ फेरीवालों ने यह भी जानकारी दी कि उन्होंने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि योजना) के अंतर्गत बैंकों से ऋण लिया है, जिसकी किस्त चुकाने में अब उन्हें कठिनाई हो रही है। फेरीवालों का कहना है कि लगातार हो रही कार्रवाई के कारण कई परिवारों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उनका आरोप है कि प्रशासन द्वारा उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में दिनेश जाधव, रोहिदास देवाडे, स्वप्निल सूर्यवंशी, संतोष गुप्ता, राम शिंदे, सुदामा गुप्ता सहित कई अन्य विक्रेता उपस्थित थे। फेरीवालों ने प्रशासन से मांग की है कि सभी सड़कों पर समान नियम लागू किए जाएं और पात्र फेरीवालों को आजीविका चलाने की अनुमति दी

लोक अदालत से न्याय सुलभ, लैंगिक समानता से समाज सशक्त: सिविल जज सुशील सिंह

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। समाज में न्यायिक जागरूकता और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर, दीवानी न्यायालय जौनपुर एवं Mohammad Hasan P.G. College के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय जागरूकता संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। संगोष्ठी में राष्ट्रीय लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत, लैंगिक समानता तथा पीसीपीएनडीटी अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता दीवानी बार काउंसिल जौनपुर के अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव ने की। उन्होंने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि लैंगिक समानता केवल सामाजिक आवश्यकता ही नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व भी है, जिसे सामूहिक प्रयास से सशक्त करना होगा। मुख्य वक्ता के रूप में सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर सुशील कुमार सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत एवं स्थायी लोक अदालत न्याय को सरल, त्वरित और किफायती बनाती हैं, जिससे आमजन को सुलभ न्याय प्राप्त होता है। उन्होंने Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act (पीसीपीएनडीटी अधिनियम) के प्रावधानों की जानकारी देते हुए भ्रूण लिंग परीक्षण को दंडनीय अपराध बताया और बालिका संरक्षण के लिए समाज से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम संयोजक डॉ. अब्दुल कादिर खाँ ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षा और जागरूकता ही लैंगिक भेदभाव समाप्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। अतिथियों को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल डॉ. दिलीप सिंह ने कहा कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम का कठोर अनुपालन संतुलित लिंगानुपात के लिए आवश्यक है। दीवानी बार काउंसिलिंग के मंत्री उस्मान अली ने विधिक पेशे से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी पर बल देते हुए समाज में न्याय और समानता की भावना सुदृढ़ करने का आह्वान किया। लोक अदालत सदस्य रजनी सिंह ने महिलाओं और बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा को सामूहिक जिम्मेदारी बताया।

संगोष्ठी के दौरान वक्ताओं ने घटते बाल लिंगानुपात पर चिंता व्यक्त करते हुए लोक अदालत की उपयोगिता और उसके लाभों को विस्तार से समझाया। कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित खेल महोत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। वहीं छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति गीत, समूह नृत्य और सामाजिक संदेश पर आधारित नाटक प्रस्तुत कर वातावरण को भाव-विभोर कर दिया। कार्यक्रम का संचालन अहमद अब्बास खान ने प्रभावी ढंग से किया। इस अवसर पर विजय श्रीवास्तव (लोक अदालत सदस्य), वरिष्ठ पत्रकार आर.पी. सिंह, डॉ. जीवन यादव, डॉ. ममता सिंह, डॉ. नीलेश सिंह, अभिषेक श्रीवास्तव, डॉ. संतोष सिंह, प्रवीण यादव, तकरीम फातमा, आदिति मिश्रा, अंकित यादव, उमरा खान, फरहीन बानो सहित महाविद्यालय परिवार के सदस्य एवं छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का गरिमामय समापन हुआ।

स्नेहा दुबे पंडित ने वसई विरार महानगर पालिका मेयर की बैठक

वसई । वसई विरार सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में मेयर अजीव यशवंत पाटिल के साथ वसई विधायक स्नेहा दुबे पंडित की गुडविल मीटिंग हुई। इस मीटिंग के दौरान, शहर में अलग-अलग डेवलपमेंट के कामों, इंफ्रास्ट्रक्चर, नागरिकों की बेसिक समस्याओं के साथ-साथ पेंडिंग मामलों पर पॉजिटिव और गहरी चर्चा हुई। स्नेहा दुबे पंडित ने वसई-विरार शहर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन से काम करने का अपना कमिटमेंट जताया। इस मौके पर स्नेहा दुबे पंडित,नगर सेविका श्रीमती अपर्णा पाटिल,छोटू आनंद और मनोज गुप्ता के समेत बड़ी संख्या में ऑफिस बेयरर्स और एक्टिविस्ट मौजूद थे।

मनबढ़ो ने अधेड़ को पीटा,वीडियो वायरल

-जितेन्द्र कन्नौजिया

केराकत,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। कोतवाली अंतर्गत कटहरा गांव में एक अधेड़ व्यक्ति के पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पीटने की वजय पुरानी जमीन की रंजिश बताई जा रही है।पीटने वाला युवक अधेड़ व्यक्ति पर शराब पी कर गाली देने का आरोप लगाते बेरहमी से पीट रहा है जिसके बाद पीट रहा अधेड़ व्यक्ति बेसुध होकर जमीन पर गिरते दिखाई दिया।घटना मंगलवार की रात का बताया जा रहा है वही पूरी घटना का वीडियो किसी ने बना लिया जो अब वायरल हो रही है।हालांकि ऐसे किसी वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि अखबार नहीं करता है। पीड़ित विनोद चौहान ने बताया कि जमीन का विवाद था है दिवाल से सटाकर नांद रखी गई थी जिस कारण पानी बह रहा था वहीं मना किया जिसको लेकर कहासुनी हो गई जिसपर विपक्षी लात घुसो से मारने पीटने लगा और मेरे दाहिने हाथ में गंभीर चोट आ गई।तत्पश्चात बुधवार को कोतवाली पहुंच तहरीर दी गई जिसपर गुरुवार को पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले आई।

वर्तमान समय में डिजिटल शिक्षा का महत्व बढ़ा: प्रो. रणजीत पांडेय

गांधी स्मारक पीजी कॉलेज समोधपुर में हुआ टैबलेट वितरण

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। सुईथाकला क्षेत्र के गांधी स्मारक पीजी कॉलेज समोधपुर में बृहस्पतिवार को महाविद्यालय परिसर में टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टैबलेट पाकर छात्रों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कार्यक्रम प्राचार्य प्रो.रणजीत कुमार पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। प्राचार्य ने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल शिक्षा का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। तकनीकि शिक्षा युवाओं के बहुमुखी प्रतिभा का विकास करने में अहम भूमिका निभा रही है।सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे टैबलेट विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास, ऑनलाइन अध्ययन तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने छात्र-छात्राओं से इन संसाधनों का सदुपयोग करने का आह्वान किया। संचालन नोडल अधिकारी डॉ विष्णुकांत त्रिपाठी ने किया। उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए टैबलेट वितरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया। विद्यार्थियों में विशेष उत्साह देखने को मिला तथा उन्होंने महाविद्यालय प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। मौके पर प्रो. अरविंद कुमार सिंह, डॉ अवधेश कुमार मिश्रा, डॉ पंकज सिंह, डॉ अविनाश वर्मा, डॉ आलोक प्रताप सिंह बिसेन, डॉ लालमणि प्रजापति, डॉ वंदना तिवारी, डॉ जितेंद्र सिंह तथा जितेंद्र कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।